● वर्ष-4
● अंक-93
रायपुर, बुधवार
27 नवंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» कामकाजी महिलाओं को हमेशा...

चना, मसूर एवं सरसों का होगा उपार्जन

प्रदेश के किसानों के हित में साय मंत्रिपरिषद के अहम निर्णय

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों के हित में अहम फैसला लिया है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर के महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता, हरित ऊर्जा विकास शुल्क को खत्म करने सहित 9 बड़े निर्णय लिये गये हैं।

मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन, ह्वह्रूई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन-तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकतानुसार सीधे बीज क्रय किया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट देने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम पांच साल के लिए प्रति वर्ष 01 लाख रूपए प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक पांच साल के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रावधान था, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं एवं ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

5वीं-8वीं की परीक्षाओं को केन्द्रीकृत किये जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग अधिकृत

मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने हेतु आगामी कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन किया।

मंत्रिपरिषद ने कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केन्द्रीकृत किये जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको द्वारा आगामी 5 वर्षो में एक लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता, परामर्श, क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अब तक तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यपवर्तन शुल्क प्रीमियम, अर्थदण्ड एवं भू-राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए व्यपवर्तन शुल्क एवं अर्थदण्ड से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।

बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो-भारत

ढाका। बांग्लादेश की एक कोर्ट ने हिंदू संगठन सम्मिलित सनातनी जोत के नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। इसस पहले बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन करने पर इस्कॉन के चिन्मय कृष्ण दास प्रभु पर कार्रवाई की गई थी। उनको देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में बांग्लादेश पुलिस ने ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। इसके खिलाफ हिंदू समुदाय के लोग ढाका की सड़कों पर उतर पड़े थे और जाम लगा दिया था। कई जगह से हिंसा की खबरें भी आई थीं।

इस पर अब भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, हमने बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल है।

देशद्रोह का मुकदमा हो चुका दर्ज

इससे पहले 30 अक्तूबर को बांग्लादेश में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में देशद्रोह अधिनियम के तहत चिन्मय कृष्ण दास प्रभु समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आरोप है कि 25 अक्तूबर को चटगांव के लालदीघी मैदान में सनातन जागरण मंच ने आठ सूत्री मांगों को लेकर एक रैली की थी। इस दौरान एक चौक पर स्थित आजादी स्तंभ पर कुछ लोगों ने भगवा ध्वज फहराया था। इस ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था। इसे लेकर चिन्मय कृष्ण दास पर राष्ट्रीय झंडे की अवमानना व अपमान करने का आरोप लगाया गया है।

बीते अगस्त में एक छात्र आंदोलन के चलते शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतत्व में एक कार्यवाहक सरकार बांग्लादेश में प्रशासन कर रही है, लेकिन शेख हसीना की सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद से बांग्लादेश में हिदुओं और अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं, जिनके खिलाफ अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा कई बार विरोध प्रदर्शन किए गए हैं।

अक्तूबर से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों की मांग को लेकर सनातन जागरण मंच ने चटगांव में विरोध प्रदर्शन शुरू किए थे। इसमें चिन्मय कृष्ण दास प्रभु ने कई बार सरकार पर हमला बोला।

राशन की मुफ्तखोरी बढ़ती जा रही-सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राशन की मुफ्तखोरी को लेकर तल्ख टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राशन की मुफ्तखोरी बढ़ती जा रही है। कोविड का दौर अलग था, तब प्रवासी श्रमिकों को राहत देने के लिए मुफ्त राशन दिया गया था। मंगलवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए मुफ्त राशन की मांग करने वाले एक एनजीओ की ओर दायर याचिका पर सुनवाई की। एनजीओ के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी श्रमिकों को मुफ्त राशन और राशन कार्ड देने के निर्देश दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस पर न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की पहचान और अधिकार से जुड़ा होता है। मुश्किल तब आती है जब हम मुफ्तखोरी में लिप्त हो जाते हैं। अब यह बढ़ रही है। कोविड का समय कुछ अलग था, लेकिन अब हमें इस पर विचार करना होगा।केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता के वकील भूषण की दलील पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से बंधी हुई है और जो भी वैधानिक रूप से अधिकार प्रदान किया गया है, वह दिया जाएगा। कोविड के दौरान कुछ ऐसे एनजीओ थे जिन्होंने महामारी के दौरान जमीनी स्तर पर काम नहीं किया और वह हलफनामे पर बता सकते हैं कि याचिकाकर्ता उन एनजीओ उनमें से एक है। पीठ ने कहा कि यह मुकदमा विरोधात्मक नहीं है और अदालत दोनों पक्षों को समायोजित करने के लिए एक सामान्य आधार खोजने की कोशिश करेगी। मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी। मामले में दो सितंबर को शीर्ष अदालत ने केंद्र से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा था जिसमें प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड और अन्य कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए उसके 2021 और उसके बाद के निर्देशों के अनुपालन के बारे में विवरण दिया गया हो।

समाज कल्याण मंत्री राजवाड़े ने नवा रायपुर स्थित नवीन शासकीय आवास में किया गृह प्रवेश

महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने नया रायपुर स्थित नवनिर्मित शासकीय आवास में अपने परिजनों के साथ विधिवत पूजा-अर्चना कर गृह प्रवेश किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंत्री श्रीमती राजवाड़े को उनके नए आवास में प्रवेश के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। गृह प्रवेश समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक एवं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, किरण देव सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण ने भी महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े को अपनी शुभकामनाएं और बधाई दी।

प्रमुख समाचार

राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक मामले पर कोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस जनहित याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। कोर्ट ने मंत्रालय से तीन हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 19 दिसंबर 2024 को है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने कहा कि उन्होंने सभी दस्तावेज और सबूत अदालत को सौंप दिये हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो भी कहा है वह सही पाया जाएगा।% मामले की जांच सीबीआई ने भी की है, अहम सबूत दिए गए हैं। गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है, 19 दिसंबर अगली तारीख है, तब तक गृह मंत्रालय को भी अपना जवाब दाखिल करना होगा। इससे पहले 6 नवंबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया गया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही एक जनहित याचिका पर गांधी की नागरिकता की सीबीआई जांच शुरू की गई थी। जब याचिकाकर्ता, कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता, ने कहा कि उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है, तो मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि वह नहीं चाहता कि कोई विरोधाभासी आदेश पारित किया जाए।

नहीं चाहिए ईवीएम बैलेट पेपर पर होने चाहिए चुनाव-खड़गे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को चुनावों में मतपत्रों की वापसी को चिह्नित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा जैसे अभियान का आह्वान किया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी के संविधान दिवस कार्यक्रम में उन्होंने कहा, हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें मतपत्र चाहिए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 में से 230 सीटों पर जीत हासिल की, जिसके बाद कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने चुनाव के संचालन में गड़बड़ी का आरोप लगाया। कांग्रेस के महाराष्ट्र पर्यवेक्षक और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने राज्य में ईवीएम हैकिंग का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर वार करते हुए खड़गे ने कहा कि आप (सत्ता में) आए और लूट रहे हैं और इसे अडानी, अंबानी और उनके जैसे अन्य लोगों को दे रहे हैं। इन लोगों ने कभी देश के लिए नहीं सोचा। मोदी और ये एक-दूसरे के लिए सोचते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में अडानी की बड़ी भूमिका थी।

कांग्रेस के महाराष्ट्र हारते ही इंडि गठबंधन में रार

नई दिल्ली। हरियाणा और महाराष्ट्र में अप्रत्याशित हार के बाद कांग्रेस आलोचनाओं में घिर गई है। कांग्रेस की लगातार हार के बाद, टीएमसी ने भी अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगी पर सवाल खड़े कर दिए है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस से अपने अहंकार को दूर करने और ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए कहा है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस न तो हरियाणा में और न ही महाराष्ट्र में वांछित परिणाम हासिल करने में सफल रही है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि हमें कांग्रेस से जबरदस्त उम्मीद थी कि वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अगर उन्होंने बेहतर किया होता तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी दबाव में होते। इंडिया गठबंधन तो है लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सका। और परिणाम हासिल करने में कांग्रेस की ओर से बड़ी विफलता है। उन्होंने कहा कि आज जरूरी है कि बीजेपी से लड़ना है तो इंडिया गठबंधन मजबूत हो। और इसे मजबूत बनाने के लिए एक लीडर की जरूरत होती है। अब नेता कौन हो सकता है? यही मूल प्रश्न है। कांग्रेस ने यह किया है। सारे प्रयोग हो चुके हैं, लेकिन असफल रहे हैं। महाराष्ट्र चुनावों का जिक्र करते हुए जहां राकांपा और कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन किया, बनर्जी ने कहा कि शरद पारद भी वह नहीं कर सके जो उनसे अपेक्षित था।

शपथ से पहले हेमंत सोरेन की मोदी-अमित शाह से मुलाकात

नई दिल्ली। झारखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री और झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और पार्टी नेता कल्पना सोरेन के साथ मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संसद में शाह से मुलाकात के बाद सोरेन ने कहा कि आप सभी को नमस्कार। आने वाले दिनों में भी बैठकें होंगी। बहुत सारी चीजें हैं। हमें अपनी सरकार बनानी है। हम यहां आशीर्वाद के लिए आये हैं। झारखंड में नई सरकार बनाने की तैयारी के बीच सोरेन ने केंद्र के साथ आगे की चर्चा का संकेत दिया। राज्य विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल करने के बाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और नवनिर्वाचित सीएम हेमंत सोरेन 28 नवंबर को शपथ लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले सोमवार को उन्होंने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके अलावा, उन्होंने अगली विधानसभा में सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। गुरुवार को हेमंत सोरेन के साथ कई अन्य विधायक भी शपथ ले सकते हैं।

ट्रंप वापस ले सकते हैं अदाणी के खिलाफ मामला, दावा

न्यूयॉर्क। भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी पर अमेरिका की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर भारतीय अमेरिकी वकील रवि बत्रा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद अदाणी के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामले को वापस ले सकते हैं। रवि बत्रा ने कहा कि हर नए राष्ट्रपति के पास एक नई टीम होती है। डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर किसी भी ऐसे मुकदमे और मामलों को निष्प्रभावी कर सकते हैं जो विरोधी को निशाना बनाने के लिए कानून का सहारा लेने पर आधारित है। कानून का अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना अमेरिका के संघीय संविधान द्वारा दी गई कानून के समान संरक्षण की गारंटी के लक्ष्य को नकारता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को गौतम अदाणी भारतीय सरकार के साथ उठा सकते हैं और अनुरोध कर सकते हैं कि वह इस पर ट्रंप प्रशासन से बात करे। यदि आपराधिक या दीवानी आरोपों को बेबुनियाद या दोषपूर्ण माना जाता है तो राष्ट्रपति ट्रंप का नया न्याय मंत्रालय और एसईसी (प्रतिभूति और विनिमय आयोग) आपराधिक और दीवानी मामलों को वापस ले सकता है।

5 साल तक महाराष्ट्र के सीएम रहेंगे फडणवीस, शिंदे डिप्टी सीएम

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को भारी जीत दिलाने के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने मंगलवार सुबह सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया। अब माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि, शिंदे ने भी अपनी दावेदारी नहीं छोड़ी है। चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 सदस्यीय विधानसभा में 235 सीटों पर भारी जीत हासिल की।

सूत्रों के मुताबिक, दो परिदृश्य हैं जिन पर काम किया जा रहा है। पहले परिदृश्य में, एकनाथ शिंदे पूरे पांच साल के लिए देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री रहेंगे। और ढाई साल में कोई रोटेशन नहीं होगा। जिस तरह फडणवीस ने ढाई साल तक उपमुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, उसी तरह एकनाथ शिंदे भी सीएम के उपमुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक

ऐसी संभावना है कि शिंदे को शहरी विकास यानी PWD मंत्रालय दिया जा सकता है, जो एक बहुत बड़ा मंत्रालय है। समृद्धि महामार्ग जैसी योजना इसी मंत्रालय की देन है।

अटकलें यह भी हैं कि अजित पवार को वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है और वह डीवाई सीएम भी बने रहेंगे। देवेन्द्र फडणवीस के कार्यभार संभालने के साथ गृह मंत्रालय भाजपा के पास रहेगा। और दूसरा परिदृश्य जो राजनीतिक हवा में बन रहा है वह यह है कि एकनाथ शिंदे के करीबी उदय सामंत, शंभुराजे देसाई या दीपक केसरकर आने वाले समय में उपमुख्यमंत्री बन सकते हैं और एकनाथ शिंदे नई दिल्ली जा सकते हैं। हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 132 सीटें जीतीं, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना और राकांपा क्रमश- 57 और 41 सीटों पर विजयी रहीं। कई छोटे संगठन भी गठबंधन का हिस्सा हैं।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए शिवसेना नेता शंभुराज देसाई ने कहा कि एक शिवसैनिक होने के नाते उनका मानना ??है कि पार्टी के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे को सीएम पद मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी महायुति का नेतृत्व कौन करेगा और महायुति का सीएम चेहरा कौन होगा - हमारे तीन नेता एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एक साथ बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। वे जो भी निर्णय लेंगे उसे महायुति के सभी विधायक मानेंगे और वही निर्णय लागू किया जायेगा।

एकनाथ शिंदे नाखुश हैं -रामदास

महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर केंद्रीय मंत्री और आरपीआई-अठावले अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र विवाद जल्द खत्म होना चाहिए क्योंकि बीजेपी आलाकमान ने फैसला किया है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाना चाहिए, लेकिन एकनाथ शिंदे नाखुश हैं और उनकी नाराजगी दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विवाद जल्द ख़त्म होना चाहिए। बीजेपी आलाकमान ने फैसला किया है कि देवेन्द्र फडणवीस को सीएम बनाया जाए लेकिन एकनाथ शिंदे नाखुश हैं और उनकी नाराजगी दूर करने की जरूरत है।

अठावले ने कहा कि बीजेपी के पास इतनी सीटें हैं कि बीजेपी भी नहीं मानेगी। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को 2 कदम पीछे हटना चाहिए, जैसे देवेन्द्र फडणवीस 4 कदम पीछे हटे और उनके नेतृत्व में काम किया। एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम या कम से कम केंद्रीय मंत्री बनना चाहिए। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बारे में जरूर सोचेंगे और जल्द ही कुछ फैसले लेने होंगे। हमें एकनाथ शिंदे और उनके 57 विधायकों की बहुत जरूरत है।

उन्होंने कहा कि जल्दी से समझौता होना चाहिए और बड़े विश्वास के साथ कैबिनेट का विस्तार होना चाहिए, लेकिन मेरी पार्टी को उस कैबिनेट में एक मंत्री पद मिलना चाहिए। मैंने ऐसी ही मांग देवेन्द्र फड़णवीस से की थी। मुख्यमंत्री समेत महाराष्ट्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में चार से पांच दिन और लग सकते हैं। 2 दिसंबर को भव्य कार्यक्रम आयोजित करने पर चर्चा चल रही है, बड़े पैमाने पर समारोह की तैयारी जोरों पर है। सूत्रों से पता चला है कि जहां 2 दिसंबर को कार्यक्रम आयोजित करने पर चर्चा चल रही है, लेकिन आयोजन में देरी का मुख्य कारण मुख्यमंत्री पद को लेकर सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर चल रही खींचतान है।

यह गतिरोध नेतृत्व को लेकर भाजपा और शिवसेना गुटों के बीच मतभेदों के कारण उत्पन्न हुआ है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखने पर अड़े हुए हैं और उनके नेतृत्व को गठबंधन की शानदार जीत के लिए महत्वपूर्ण बताते हैं। सेना के प्रवक्ता नरेश म्हस्के ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था और उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखना गठबंधन की एकता और नेतृत्व का सम्मान होगा।

कवर्धा में बारदाना की समस्या, किसान संघ ने सौंपा ज्ञापन

कवर्धा में किसानों ने बारदाना की समस्या का जल्द निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी

कवर्धा। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू हो चुकी है। धान खरीदी शुरू हुए करीब 15 दिन भी नहीं बीते हैं और बारदाना की समस्या आ रही है। किसानों का कहना है कि उन्हें धान उपार्जन केन्द्रों में बारदान देने कहा जा रहा है। हालांकि सरकार ने किसानों को उनके बारदाने की 25 रुपए कीमत अदा करने की बात कही है।

किसानों का कहना है कि बारदाना का बाजार मूल्य 25 रुपए से ज्यादा है। इससे किसानों को सीधा नुकसान होगा। सोसायटियों में किसान और प्रबंधक के बीच कहासुनी होने की स्थिति भी बन रही है। ऐसे में समृद्ध किसान संघ के सैकड़ों लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से बारदाने की समस्या को दूर करने ज्ञापन सौंपा है। जल्द समस्या दूर नहीं होने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। समृद्ध किसान संघ के लोगों का आरोप है कि धान खरीदी को कुछ ही दिन हुए हैं और बारदाने की समस्या होने लगी है। सोसायटियों में किसानों को बारदान देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सरकार द्वारा बारदाना का 25 रुपए देने की बात की जा रही रही है, लेकिन बारदाने का बाजार मूल्य 25 से अधिक है। ऐसे में किसानों को नुकसान हो रहा है। प्रशासन बारदाने की समस्या को दूर करे वरना आने वाले समय में हम सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे। वहीं कलेक्टर ने समस्या दूर करने आश्वासन दिया है।

दरअसल शासन ने कबीरधाम जिले में धान खरीदी का लक्ष्य 06 लाख 84 हजार 157 मीट्रिक टन रखा है। शासन के लक्ष्य के मुताबिक धान खरीदी करने के लिए प्रशासन को 33 हजार 208 बारदाना की जरुरत है। इसका 50 पर्सेंट नया बारदाना सरकार उपलब्ध करा रही है। वहीं 50 पर्सेंट पुराना बारदाना जिला प्रशासन को सेवा सहकारी समिति, पीडीएस दुकान और राइस मिलर्स से जुटाना है।

पीडीएस दुकान और सेवा सहकारी समितियों द्वारा बारदाना दिया जा रहा है,

लेकिन राइस मिलर्स द्वारा बारदान देने से इंकार कर दिया गया है। ऐसे में धान खरीदी प्रभावित होने की आशंका है। धान खरीदी पोर्टल में जब तक नया पुराना दोनों बारदाना नहीं होता, सिस्टम तौल को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए दोनों बारदाना होना अनिवार्य है।

समृद्ध किसान संघ ब्लॉक अध्यक्ष रंजित साहू ने कहा शासन प्रशासन को अगर बारदाना नहीं मिल पा रहा है तो किसान को कैसे मिलेगा। इसी समस्या को लेकर हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि दो चार दिन समस्या रहेगी, उसके बाद समस्या हल हो जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राइस मिलर्स को धान का चावल बनाने प्रति क्विंटल 1200 रुपए मानदेय दिया जाता था, जिसको अब घटा कर विष्णु देव सरकार ने 600 रुपए निर्धारित किया है। इससे मिलर्स नाराज हैं और प्रशासन को बारदाना देने से इंकार कर रहे है। हालांकि सरकार और मिलर्स के बीच बातचीत चल रही है।

जिला विपणन अधिकारी किशोर चंद्रा ने बताया कि समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए नया पुराना दोनों बारदाना का उपयोग करना है। शासन द्वारा आवश्कता के अनुसार नया बारदाना उपलब्ध करा दिया गया है। पुराना बारदाना सोसायटी, पीडीएस दुकान और राइस मिलर्स से लिया जाना था, लेकिन राईस मिलर्स द्वारा बारदाना नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण समस्या आ रही है। कुछेक जगहों पर ज्यादा समस्या है। वहां अन्य जगह से बारदाना उपलब्ध कराया जा रहा है।

नया बारदाना में समस्या नहीं है। पुराने बारदाने सोसायटी, पीडीएस दुकान और राइस मिलर्स से मिलते हैं। लेकिन राइस मिलर्स बारदाना नहीं दे रहे हैं। पीडीएस दुकान और समितियों से बारदाना कलेक्ट कर रहे हैं। मिलर्स के मना करने से यह समस्या आ रही है। किसानों पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है-किशोर चंद्रा, जिला विपणन अधिकारी जिला विपणन अधिकारी किशोर चंद्रा ने यह भी कहा कि किसान अगर बारदाना लेकर आ रहे हैं तो उनको उसका पेमेंट किया जाएगा। किसानों को बारदाने के लिए 25 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है।

बलरामपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस में मनाया गया संविधान दिवस

बलरामपुर। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई।

बलरामपुर के डिप्टी कलेक्टर प्रमोद गुप्ता ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि आज संविधान दिवस है। हर साल 26 नवंबर को संविधान की शपथ लेते हैं। आज यहां बलरामपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में सभी अधिकारी कर्मचारी पहुंचे और सामूहिक रूप से संविधान दिवस की शपथ ली गई है।

26 नवंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। 26 जनवरी, 1950 से यह संविधान प्रभावी है। इस संविधान ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को अपनाया गया था। संविधान भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला है।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सैकड़ों बेगुनाह नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी। आज मुंबई आतंकी हमले की सोलहवीं बरसी भी है। डिप्टी कलेक्टर प्रमोद गुप्ता ने कहा कि हम सभी इस आतंकी हमले की निंदा करते हैं और हमेशा ही इस हमने की निंदा की जाएगी।

मनियारी नदी में दिनदहाड़े हो रहा अवैध रेत खनन

■ **जिम्मेदारों की चुप्पी पर उठे सवाल**

मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के सांवतपुर इलाके में मनियारी नदी से दिनदहाड़े रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिससे खनन माफियाओं का हौसला बुलंद दिख रहा है। महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरगांव थाना क्षेत्र में यह अवैध कारोबार प्रशासन की नाक के नीचे जारी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही।

स्थानीय लोगों के अनुसार, आधा दर्जन ट्रैक्टर-ट्रालियां प्रतिदिन नदी से रेत भर रही हैं। तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मनियारी नदी में खुलेआम रेत का उत्खनन हो रहा है।

ग्रामीणों ने इस अवैध कारोबार की शिकायत कई बार सरगांव थाने में की है, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इससे स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। उनका आरोप है कि संबंधित अधिकारियों की मौन स्वीकृति इस अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रही है।

सांवतपुर के सरपंच प्रतिनिधि मनोज उइके का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे मनियारी नदी पर

हो रहे अवैध रेत उत्खनन को रोकने की मांग कर रहे हैं।

इस मामले को लेकर सरगांव थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने कहा, मेरे संज्ञान में यह मामला नहीं है। मैं फिलहाल मुंगेली में हूं। जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम बी।आर। ठाकुर ने कहा, नायब तहसीलदार को मौके पर भेजकर जांच और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

रेत और मुरुम के अवैध परिवहन कर रहे 9 हाईवा जब्त

अभनपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में खनिज विभाग ने बीती रात गौण खनिजों के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खनिज विभाग की टीम ने बीती रात जिले के अभनपुर इलाके में रेत का अवैध परिवहन कर रहे 7 हाईवा और नवा रायपुर से 2 हाईवा मुरुम को जप्त कर पुलिस चौंकी उपरवारा को सुपुर्द कर दिया है। यह कार्रवाई रायपुर कलेक्टर के आदेश और खनिज विभाग के उप संचालक के।के। गोलघाटे के निर्देश पर की गई। खनिज विभाग के सुपरवाइजर सुनील दत्त शर्मा के नेतृत्व में टीम ने गरियाबंद जिले से रेत का और नवा रायपुर से मुरुम का अवैध परिवहन कर रहे हाईवा वाहनों को पकड़ा। इन वाहनों को पुलिस चौकी उपरवारा के सुपुर्द कर दिया गया।

जब्त हाईवा बेमेतरा, रायपुर और दुर्ग जिलों के बताए जा रहे हैं। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार है- CG 04 NW 5583, CG 04 PB 9982, CG 04 PS 3972, CG 04 3971, CG 25 M 4501, CG 22 T 9722, CG 97 CE 5668, CG 07 BR 6343, CG 25 M 3396

इस कार्रवाई में वीरेंद्र बेलचंदन, सैनिक रूपेश चंद्राकर, राजू बर्मन, गोलू वर्मा और जितेंद्र केशरवानी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

अभनपुर क्षेत्र में लंबे समय से रेत और मुरुम का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है। जनप्रतिनिधियों और खनिज माफिया की सांठगांठ की वजह से यह कारोबार फल-फूल रहा है। हालांकि, जनाक्रोश को देखते हुए खनिज विभाग कभी-कभी कार्रवाई कर अपनी सक्रियता दिखाने का प्रयास करता है।

उड़नदस्ता टीम का बड़ी कार्रवाई

अनफिट और बिना परमिट के बसों पर कसा शिकंजा

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। जिले में बिना फिटनेस और परमिट के संचालित हो रही बसों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसा है। जनकपुर क्षेत्र में मंगलवार को परिवहन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने कार्रवाई करते हुए बिना फिटनेस और परमिट के संचालित बस को पकड़ा है। अनफिट बस को जब्त कर जनकपुर पुलिस थाना के परिसर में खड़ा किया गया है।

उड़नदस्ता टीम को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बैकुंठपुर से जनकपुर जाने वाली कुछ बसें बिना फिटनेस और परमिट के संचालित की जा रही है। इस तरह यात्रियों की जान को जोखिम में डाल कर बस संचालन किया जा रहा है। शिकायत मिलने पर उड़नदस्ता टीम ने मंगलवार को जनकपुर कोटाडोल मार्ग पर संचालित समीर बस पर नियमानुसार कार्रवाई की।

आशंबर तेज द्विवेदी ने कहा हमने जनकपुर कोटाडोल और जनकपुर मनेंद्रगढ़ मार्ग पर बिना फिटनेस और परमिट के बसों की जांच की। एक बस को नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया, जिसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है। बस को जब्त कर जनकपुर पुलिस थाना परिसर में खड़ा किया गया है। आगे भी ऐसा चेकिंग अभियान जारी रहेगा। जनकपुर क्षेत्र में

लंबे समय से बिना फिटनेस और परमिट वाली बसों का संचालन किया जा रहा था। इस वजह से जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन अनफिट और बिना परमिट वाली बसों के खिलाफ इस कार्रवाई के बाद यात्रियों में सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ा है। परिवहन विभाग अंबिकापुर के अपर परिवहन आयुक्त आशंबर तेज द्विवेदी ने जानकारी दी कि यह कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देश पर की गई है। अंबिकापुर के अपर परिवहन आयुक्त आशंबर तेज द्विवेदी ने कहा है कि आगे भी ऐसा चेकिंग अभियान जारी रहेगा। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि जनकपुर क्षेत्र में बिना परमिट और फिटनेस वाले वाहनों पर लगातार कड़ी नजर रखी जाएगी।

गाड़ियों से फट फट आवाज आई तो खैर नहीं

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गाड़ियों पर मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बीते दिनों यातायात पुलिस ने लगातार गाड़ियों का चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान करीब 500 बुलेट और दूसरे बाइक्स की जांच की गई। जिसमे 60 गाड़ियां ऐसी मिली जिसमें साइलेंसर मोडिफाइड किया गया था। पुलिस ने सोमवार को ऐसे मोडिफाइड साइलेंसर पर बुलडोजर चलवाया। यातायात डीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि धमतरी पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देश पर महीनेभर से यातायात चेकिंग अभियान चलाया गया। लगभग 500 से ज्यादा गाड़ियों की चेकिंग की गई। जिसमें 60 गाड़ियों में मोडिफाइड साइलेंसर लगे मिले। इन साइलेंसर को गाड़ियों से निकाला गया और उन्हें जब्त कर उन पर बुलडोजर चलाया गया। मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि 20 से ज्यादा वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। 12 वाहन चालकों को कोर्ट में पेश किया गया। जिसमें न्यायालय ने 76 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

14 दिसंबर को साल की आखिरी लोक अदालत

बेमेतरा। बेमेतरा जिले में इस साल की चौथी व अंतिम नेशनल लोक अदालत 14 दिसंबर को होगी। इस लोक अदालत में राजीनामा कर मामले निपटाए जाएंगे। इस आयोजन के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा बृजेन्द्र कुमार शास्त्री की अध्यक्षता में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निधि शर्मा, न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारी के साथ बैठक हुई। बैठक में बधिक से अधिक प्रकरण को चिन्हांकित करने व पूर्ण प्रयास कर निराकरण किए जाने निर्देश दिए गए। राजीनामा के आधार पर निराकरण के लिए राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, चेक बाउंस के मामले, मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, निष्पादन, बीमा, भरण पोषण के प्रकरण, परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण, सिविल विवाद, विद्युत, जलकर व सम्पत्ति कर, टेलीफोन, बैंक रिकवरी प्रकरण तथा राजस्व प्रकरणों को नियत किया गया है।एसपी से प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के पक्षकारों पर नोटिस की तामिली एवं उनके साथ सौहार्दपूर्ण रूप से राजीनामा करने पर चर्चा की गई।

सहेली को हसीन सपने दिखाकर ठगे 31 लाख रुपये

जगदलपुर। जगदलपुर में कॉलेज में पढ़ने वाली एक सहेली ने अपने सहेली को ट्रेडिंग कंपनी में पैसा लगाने पर दोगुना पैसा मिलने की बात बताई, साथ ही विदेश दौरे की जानकारी भी दी, जिसके बाद सहेली के बातों में आकर अपनी जमा पूंजी दे दी। जहाँ ना तो पैसा मिला और ना ही लाभ, जिसके बाद बोधघाट थाने में मामला दर्ज किया गया। मामले की जानकारी देते हुए बताया गया कि आड़ावाल ओरना कैम्प निवासी अलका दास ने बोधघाट थाने में मामला दर्ज कराया कि उसके साथ पढ़ने वाली अनुषा श्रीवास्तव ने 1 वर्ष पहले फेसबुक के माध्यम से अलका से उसका फोन नंबर लेने के बाद उसे बताया कि उसका पति संदीप रायगढ़ के जिंदल कंपनी में काम करने के साथ ही ट्रेडिंग कंपनी में काम करता है, जहाँ उसे हर माह 4 से 5 लाख की कमाई होती है। सहेली की बातों में आकर अलका ने 1 मई 2023 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक कुल 22 लाख 50 हजार संदीप के फोन पे पर तथा रवि के फोन पे पर 9 लाख रुपये भेजे, इस तरह अलका ने कुल 31 लाख 50 हजार रुपये दे दिया।

भनवारटंक स्टेशन के पास मालगाड़ी के 23 डिब्बे बेपटरी

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले के भनवारटंक रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को कोयला से भरे मालगाड़ी के डिब्बे बेपटरी हो गए और देखते ही देखते इंजन सहित 23 डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल रेलवे के कर्मचारी और अधिकारीगण वहां पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। इस हादसे के बाद रेलवे ने 6 ट्रेनों को कैंसिल और 9 ट्रेनों के रुटों में बदलाव कर दिया है। यह मालगाड़ी बिलासपुर की ओर जा रही थी तभी यह हादसा हो गया। बिलासपुर कटनी रेल मार्ग की कई यात्री ट्रेनें अलग-अलग रेलवे स्टेशन में रोकी गई।

भिलाई में सुप्रीम कोर्ट के वकील के घर चोर

दुर्ग। जिले के चौहान ग्रीन वैली निवासी सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अमृता कामेश्वर श्रीवास्तव के घर पर कथित रूप से चोरी का असफल प्रयास हुआ। सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की तस्वीर कैद होने के बाद मामले की शिकायत एसपी जितेंद्र से की गई है। दरअसल अधिवक्ता इन दिनों कोर्ट के काम से दिल्ली में हैं। इस बीच उनके सूने मकान में आरोपी रेकी करते देखा गया है। आरोपी सूने मकान की खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। दिल्ली में अपने मोबाइल पर सीसीटीवी एक्सेस कर अधिवक्ता ने फुटेज देखा। इसके बाद एसपी जितेंद्र शुक्ला को इसकी जानकारी दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि युवक चोरी या रेकी करने आया था, यह अधिकृत रूप से भले नहीं कहा जा सकता, लेकिन शहर में जिस तरह सूने मकानों को आरोपी निशाना बनाकर चोरी करते रहे हैं। उसके मद्देनजर आम नागरिक को भी जागरूक रहते हुए हर संदिग्ध मामलों की जानकारी दी जानी चाहिए। इसलिए वे जानकारी दे रहे हैं।

शहरी क्षेत्र में बाघ के घुसने से मचा हड़कंप

बलौदाबाजार। छह महीनों से बार नवापारा जंगल में घूम रहा बाघ शहरी क्षेत्र में पहुंचा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने टेक्युलाइजर कर बाघ को निश्चेत किया और अब उसे संरक्षित जगह में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि बलौदाबाजार जिले में विगत छह महीनों से बार नवापारा क्षेत्र में बाघ के आने से वन्य पशु प्रेमियों में खुशी का माहौल था कि अब जिले में भी बाघ की दहाड़ सुनने को मिल रही। यह खुशी आज काफुर हो गई, जब बाघ कल शाम से लवन क्षेत्र के ग्राम कोरदा में दिखाई दिया। वहीं आज कसडोल कॉलेज के पास ग्राम गोरदा में बाघ दिखाई दिया, जिससे लोग दहशत में है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम बाघ के हर मूवमेंट पर नजर रख रही थी और लोगों को उसे छेड़ने से मना कर रही थी। वहीं आज सुबह से ही टीम उसे पकड़ने की कवायद कर रही थी। टीम को कुछ देर पहले सफलता मिली और बाघ को टेक्युलाईजर कर निश्चेत कर पकड़ लिया।

सोशल मीडिया पर आरक्षक ने भड़काऊ पोस्ट किया, एसपी ने किया सस्पेंड

कबीरधाम। कबीरधाम जिले में सोशल मीडिया में सामाजिक द्वेष फैलाना वाला पोस्ट करना एक आरक्षक पर भारी पड़ गया है। सोमवार को एसपी ने आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच बैठा दिया है। एसपी ऑफिस से मिली जानकारी अनुसार थाना पिपरिया के आरक्षक अशोक चंद्रवंशी द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए ऐसे कृत्य किए गए, जो सामाजिक सौहार्द को भंग करने और हिंसात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास थे। यह कृत्य न केवल पुलिस विभाग की आचार संहिता और अनुशासन का उल्लंघन है, बल्कि पुलिसकर्मियों से अपेक्षित नैतिक और पेशेवर जिम्मेदारियों के प्रति घोर लापरवाही को भी दर्शाता है।

थाना प्रभारी पिपरिया द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि आरक्षक अशोक चंद्रवंशी द्वारा सोशल मीडिया पर

ऐसे पोस्ट किए गए, जिनसे समाज में वैमनस्यता और तनाव उत्पन्न हो सकता था। पुलिस मुख्यालय द्वारा सोशल मीडिया उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका उल्लंघन करते हुए आरक्षक ने विभागीय मर्यादाओं और निर्देशों की अवहेलना की।

जिले के प्रभारी एसपी धर्मेंद्र सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरक्षक अशोक चंद्रवंशी को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच के उपरांत कदाचार में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया है कि वे सोशल मीडिया का उपयोग करते समय विभागीय नियमों का कड़ाई से पालन करें। अपने आचरण से समाज में पुलिस विभाग की छवि को मजबूत करें। उन्होंने यह भी कहा कि अनुशासनहीनता या कर्तव्य के प्रति लापरवाही के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। यह कार्रवाई पुलिस विभाग के अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखने की दिशा में एक कड़ा संदेश है।

अब धर्मेंद्र सिंह होंगे कबीरधाम जिले के नए कप्तान

राज्य सरकार ने आईपीएस अधिकारियों का तबादला सूची जारी की है। इसमें कबीरधाम जिले में एसपी को पदस्थ किया गया है। खास बात यह है कि

कबीरधाम जिले से कवर्धा विधायक और डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा के जिले में दो माह के भीतर दो एसपी बदले जा चुके हैं। अब यहां प्रभार पर चल रहे धर्मेंद्र सिंह को जिले का पूर्ण प्रभार दिया गया है। ये दो माह के भीतर तीसरे एसपी होंगे।

दरअसल, लोहारीडीह कांड के बाद बहुचर्चित एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव को 20 सितम्बर को हटा दिया गया था। इनके जगह में राजेश अग्रवाल को भेजा गया। लेकिन, वे भी कुछ दिनों के बाद लंबे समय के लिए अवकाश में चले गए। ऐसे स्थिति में 15 वी बटालियन बीजापुर के कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह छवई को प्रभार दिया गया। वे अब प्रभार के बाद पूर्ण रूप से एसपी होंगे। बता दे कि राजेश अग्रवाल और धर्मेंद्र सिंह 2012 बैच के प्रमोटी आईपीएस अधिकारी है। धर्मेंद्र सिंह पूर्व में बेमेतरा और महासमुंद के एसपी भी यह चुके है।

टॉयलेट के बहाने पंचू फरार, चोर ने करा दिया पुलिस वाले को सस्पेंड

धमतरी। जिला अस्पताल से विचाराधीन कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस के आला अफसरों ने सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया है। फरार कैदी पंचू के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की ली है। पुलिस के मुताबिक पंचू ऊर्फ पंचराम निषाद चोरी के आरोप में पकड़ा। आरोपी चोर 15 सितंबर से ही जेल में बंद रहा। पुलिस अभिरक्षा से फरार होने वाले दिन उसने पेद दर्द की शिकायत जेल प्रबंधन से की। शिकायत के बाद उसे जिला अस्पताल धमतरी लाया गया।

अस्पताल में आरोपी चोर ने कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। कैदी के साथ आए जेल प्रहरी ने कैदी को टॉयलेट में भेज दिया और खुद बाहर खड़ा रहा। इसी दौरान पुलिसवाले की आंखों में धूल झोंककर विचाराधीन कैदी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोर पहले भी पुलिस की अभिरक्षा से फरार हो चुका है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने शौचालय के भीतर ही अपनी हथकड़ी किसी तरह से खोल ली और फरार हो गया। जेलर एस के डहरिया ने कहा चोरी और धोखाधड़ी के केस में पंचराम निषाद विचाराधीन कैदी है। पेट दर्द की शिकायत के बाद उसे एंबुलेंस से अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने तीन घंटे तक बेड रेस्ट लिखा। आरोपी ने शौचालय जाने की बात कही जिसके बाद उसे टॉयलेट भेजा गया। टॉयलेट में ही उसने हथकड़ी खोल ली और मौके से फरार हो गया। जेलर एस के डहरिया ने बताया कि लापरवाही के आरोप में प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया है। सिटी कोतवाली के प्रभारी राजेश मरई ने कहा कि जेल प्रहरी जनार्दन भोई ने विचाराधीन कैदी के खिलाफ शिकायत लिखाई है।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल ने किया अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में छत्तीसगढ़ पवेलियन का भ्रमण

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने नई दिल्ली के भारत मण्डपम में आयोजित 43वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन का भ्रमण कर प्रदर्शित वस्तुओं और उत्पादों की जानकारी ली। राज्यपाल ने पवेलियन में उपस्थित शिल्पकारों और उद्यमियों से बातचीत की एवं उन्हें प्रोत्साहित किया। राज्यपाल ने कहा कि व्यापार मेला छत्तीसगढ़ की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का एक बेहतरीन मंच है। उन्होंने राज्य की कला और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और विकास की झलक इस पवेलियन में देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ पवेलियन में राज्य की सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प, और औद्योगिक विकास को प्रदर्शित किया गया है। छत्तीसगढ़ के शिल्पकार एवं कलाकारों द्वारा बेलमेटल शिल्प, कोसा सिल्क व जैविक उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। पवेलियन में राज्य की नई औद्योगिक योजनाओं और निवेश की संभावनाओं को भी यहां दिखाया गया। इस दौरान नई दिल्ली में पदस्थ छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर श्रीमती ऋचु सैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

विशेषकर पटेल होंगे राज्य गौसेवा आयोग के नये अध्यक्ष

रायपुर। राज्य सरकार के पशुधन विकास विभाग ने कबीरधाम जिले के रहने वाले विशेषकर पटेल को राज्य गौसेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह आदेश विभाग की संयुक्त सचिव विमला नावरिया द्वारा जारी किया गया। यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ के पशुपालन और गौसेवा के क्षेत्र में नए बदलाव और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

तीन दिवसीय जॉब फेयर आज से

रायपुर। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 27, 28 एवं 29 नवम्बर तक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब फेयर के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक टेक्नोटास्क बिजनेस सॉल्यूशंस (बीपीओ) रायपुर द्वारा 12वी उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती की भर्ती सी.एस.ए. के 500 पदों पर रू. 11,750 / से 19000/- प्रतिमाह वेतनमान एवं स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज, नया रायपुर में 12वी एंव उच्च शिक्षा उत्तीर्ण आवेदकों, की भर्ती सी. एस.ए. के 450 पदों पर 10500 से 15000 प्रतिमाह वेतन पर भर्ती होगी। इस जॉब फेयर में सम्मिलित होने योग्य एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर अपने बॉयोडाटा /आधार कार्ड एवं शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क कर सकते है।

अब तक 8.95 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिलसिला अनवरत जारी है। 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी अभियान में अब तक 8.95 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 1.91 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 1575 करोड़ 16 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। अधिकारियों ने बताया कि 25 नवंबर को 47296 किसानों से 2.17 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। इसके लिए 51170 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 53439 टोकन जारी किए गए हैं।

रेंजर विनोद तिवारी को लेकर पत्रकारों में नाराजगी, वनमंत्री के नाम लिखा पत्र

बीजापुर। बीजापुर जिले के सामान्य वनमंडल के भोपालपटनम वन परिक्षेत्र में पदस्थ रेंजर विनोद तिवारी द्वारा पत्रकारों को गाली देता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ हैं। जिसके बाद मीडिया जगत से लेकर जिले के प्रशासनिक व राजनीतिक गलियारों में जहां उबाल आ गया हैं। वही इस मामले को लेकर आक्रोशित बीजापुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने बैठक आयोजित कर रेंजर विनोद तिवारी पर त्वरित कार्यवाही को लेकर वनमंत्री केदार कश्यप के नाम खुला पत्र लिखकर वनमंत्री को भेजा हैं। पत्रकारों ने वनमंत्री केदार कश्यप को लिखे खुले पत्र में कहा है कि महोदय,छत्तीसगढ़ में काबिज भाजपा की सरकार को मोदी जी की गारंटी और सुशासन की सरकार की संज्ञा दी जाती है।परंतु आपके ही विभाग में पदस्थ कुछ वन परिक्षेत्र अधिकारी सरकार की इस मंशा को मट्टीपलीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी सरकार में पत्रकारों के साथ सिर्फ बदसलूकी ही नहीं हो रही है, बल्कि उन पर फर्जी मामले भी बनाए जा रहे हैं। हाल ही में बीजापुर जिले के भोपाल पटनम में पदस्थ वन परिक्षेत्र अधिकारी विनोद तिवारी से जुड़ा एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जहां पर वे विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने गए हुए पत्रकारों के साथ मां बहन की गाली देते और उनके साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं।

रायपुर में निकली संविधान पदयात्रा, साय ने कांग्रेस पर साधा निशाना

अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस ने संविधान के साथ किया खिलवाड़ : मुख्यमंत्री

रायपुर। संविधान दिवस के 75 साल पूरे होने पर रायपुर में संविधान पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों के मुख से संविधान की बात शोभा नहीं देती। कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। अपने स्वार्थ के लिए अनावश्यक रूप से संविधान में संशोधन किए हैं। इमरजेंसी लगाकर लोगों की स्वतंत्रता का हनन किया। लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया गया।

सीएम साय ने कहा, संविधान हमारे भारत का पवित्र ग्रंथ है। देश की संस्कृति, परंपरा और इतिहास का आईना है। हमें भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ संविधान और लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। भारतीय संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर आज राजधानी के मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ कर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी को सादर नमन किया। हमारी डबल इंजन सरकार, संविधान द्वारा लोगों को प्राप्त हक और स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए संकल्पित है। आज बाबासाहेब की विरासत का प्रसार कर दुनिया को सशक्त संदेश देने का कार्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया है।

संविधान दिवस के अवसर पर अपने अधिकारों के जागरूकता के लिए निकाली गई पदयात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री टंकराम वर्मा, दयाल दास बघेल सहित विधायक और अधिकारी शामिल रहे। राजधानी के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी इस पदयात्रा में हिस्सा लिया। पदयात्रा का समापन रायपुर के अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण के साथ हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया।

राजभवन सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का किया वाचन

संविधान दिवस के अवसर पर राजभवन सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था। इस वर्ष भारत के संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। राज्यपाल के विधिक सलाहकार श्री भीष्म प्रसाद पाण्डेय, अवर सचिव सुश्री अर्चना पाण्डेय, नियंत्रक श्री संजय विश्वकर्मा सहित सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया।

नशीली दवाओं के विक्रय करने वालों पर होगी कठोर वैधानिक कार्यवाही : गृह मंत्री

रायपुर। गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में नशीली दवाओं के सेवन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो यह सुनिश्चित किया जाए। श्री शर्मा आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में प्रदेश में नशीली दवाओं के विक्रय एवं सेवन पर वैधानिक कार्यवाही करने और नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद थे।

गृह मंत्री ने प्रदेश में नशीली दवाओं के अवैधानिक वितरण की रोकथाम के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा है, कि नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए मेडिकल दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करें तथा ऐसे मेडिकल शॉप जो वैधानिक नशीली दवाओं के कारोबार में संलग्न हैं। उन पर त्वरित कठोर कार्रवाही करें। ऐसे दुकानदारों पर एफआईआर करें तथा गिरफ्तारी की भी कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करें।

गृह मंत्री ने नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों का सहयोग लेने की भी बात कही। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नियंत्रक खाद्य एवं औषधि को पुलिस अधिकारियों से समन्वय कर ड्रग इंस्पेक्टर की टीम बनाकर लगातार मेडिकल शॉपों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया।

बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुवा, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारीक, आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. प्रियंका शुक्ला, विशेष सचिव वित्त एवं सामान्य प्रशासन तथा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्री चंदन कुमार सहित वरिष्ठ पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

आरोपी याहया ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित जग्गी हत्याकांड में आरोपी बनाए गए याहया ढेबर की जमानत याचिका खारिज हो गई है। मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसला सुनाया। मिली जानकारी के अनुसार जग्गी हत्याकांड के शूटर्स जिस गाड़ी से आए थे वो गाड़ी याहया ढेबर की थी। इसके अलावा शूटर्स जिस घर (बत्रा हाउस) में रुके थे वो घर भी याहया की ही थी। इसे आधार बनाते हुए चीफ जस्टिस खन्ना ने याहया ढेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके अलावा इस मामले में 2 अन्य आरोपी अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।

इससे पहले रामावतार जग्गी हत्याकांड में आरोपी पूर्व पुलिस अफसर एएस गिल, वीके पांडेय और आरसी त्रिवेदी समेत छह लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। इन आरोपियों को छह माह पहले दोबारा जेल में दाखिल किया गया था। सभी आरोपी पांच साल से अधिक समय तक जेल में बीता चुके हैं। वकीलों ने बताया कि आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई के बाद छह आरोपियों की जमानत के आदेश दिए हैं। अब आदेश की मूल प्रति रायपुर की अदालत में जमा की जाएगी, जिसके बाद आरोपियों की जेल से रिहाई के आदेश होगा।

बता दें कि जग्गी हत्याकांड में जमानत निरस्त होने के बाद पुलिसवालों समेत जग्गी हत्याकांड समेत सभी आरोपियों को वापस जेल दाखिल करने के आदेश दिए गए थे। इस आधार पर सभी ने इस साल जून महीने में कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।

राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के क्रियान्वयन विषय पर होगा कार्यशाला

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र (सीजी.एस.सीसीसी) द्वारा नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में 28 नवंबर को सतत् आवास एवं कृषि क्षेत्रों में राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के क्रियान्वयन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला के दौरान जलवायु परिवर्तन पर एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ ही, एयर कंडीशनर तापमान विनियमन पर जागरूकता पोस्टर और जलवायु परिवर्तन से संबंधित 100 सफलता की कहानियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया जाएगा।

इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव, श्रीमती ऋचा शर्मा, आईएएस, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री उमा शंकर पांडे, जो एक सफल किसान, पारंपरिक जल संरक्षण विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो अपने अनुभव साझा करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र के नोडल अधिकारी एवं एपीसीसीएफ, श्री अरुण कुमार पांडे, आईएफएस, ने वन विभाग की हालिया उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा।

गौरतलब है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, श्री वी. श्रीनिवास राव के मार्गदर्शन में, छत्तीसगढ़ वन विभाग ने राष्ट्रीय महत्व की कई पहल की हैं। इनमें इको-रिस्टोरेशन नीति का मसौदा तैयार करना, जिससे छत्तीसगढ़, केरल के बाद यह नीति बनाने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है, और इको-डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा, विभाग ने सतत वन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कई राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

तकनीकी सत्र में अपूर्व मित्रा केपीएमजी एलएलपी, गुरुग्राम), डॉ. सुजीत कुमार (क्लिमआर्ट, बेंगलुरु), अविनाश मिश्रा, आईएएस (नगर निगम आयुक्त, रायपुर), रितेश सैनी (स्वच्छ भारत मिशन, अंबिकापुर), शशिकला (क्लस्टर लेवल फेडरेशन, स्व-सहायता समूह), आनंद सिंघानिया (अविनाश ग्रुप), अमित कुमार (ईवाई एलएलपी, नई दिल्ली), डॉ. पनीरसेल्वम एस. (पूर्व निदेशक, डब्ल्यूटीसी, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय), संकल्प शर्मा (नर्मदा नेचुरल फार्म्स, भोपाल) और डॉ. दीपक शर्मा (प्रोफेसर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर) जैसे विशेषज्ञ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

कार्यशाला में दो पैनल चर्चाएं आयोजित होंगी। पहली चर्चा सतत् आवास क्षेत्र में जलवायु-लचीले उपायों पर केंद्रित होगी, जिसमें डॉ. रघु मर्तुगुड्डे (आईआईटी मुंबई), डॉ. हिमांशु पॉपटानी (एनआईटी रायपुर), आर. संगीता (सचिव सह आबकारी आयुक्त), बसवराजू एस., आईएएस (शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग), और डॉ. कंवल कामरा सुजीत (टेरालाइव एन्वायरो टेक प्रा. लि., बेंगलुरु) भाग लेंगे। दूसरी चर्चा कृषि क्षेत्र में जलवायु-लचीले उपायों पर केंद्रित होगी, जिसमें डॉ. पनीरसेल्वम एस., जयंती बिसेन (नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट), शहला निगार, आईएएस (कृषि विभाग), प्रो. जीके दास (डीन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर), और जगदीसन एस., आईएफएस (निदेशक, बागवानी, छत्तीसगढ़) शामिल होंगे।

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने टाटा जाएगा छग के तीरंदाजी खिलाड़ी

■ **खिलाड़ियों को दिया गया सू, लोवर, टीशर्ट व ट्रैक सूट**

रायपुर। झारखंड के टाटा नगर के खेल मैदान में होने वाले राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 15 और 16 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी टाटा नगर के लिए दानापुर एक्सप्रेस और ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से रवाना होंगे। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ियों को 25 हजार रुपये इनाम के दौरान दिया जाएगा। खिलाड़ियों और कोच का टिकट कंफर्म हो गया और उन्हें यहां जाने से पहले खिलाड़ियों को सू, लोवर, टीशर्ट व ट्रैक सूट दे दिया गया है। 15 दिसंबर को रवाना होने वाली टीम की वापसी 19 दिसंबर को होगी और 16 दिसंबर को रवाना होने वाली टीम 21 दिसंबर को दानापुर एक्सप्रेस से रायपुर आएंगी। दोनों टीमों के साथ कोच के रुप में इतवारी और उमेश बघेल जाएंगे।

तीरंदाजी संघ के महासचिव आयुष मुरारका ने बताया कि झारखंड में होने वाली राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राज्य की टीम भेजने के लिए छत्तीसगढ़ तीरंदाज संघ ने रविवार को चयन ट्रॉयल आयोजित किया जिसमें विभिन्न जिले के अलावा खेल विभाग की एकेडमी और साई से लगभग 182 तीरंदाजों ने हिस्सा लिया। इसमें इंडियन आर्चरी के अलावा रिकब व कम्पाउंड डिवीजन में तीरंदाजों के बीच जमकर मुकाबले हुए। इसमें सर्वाधिक अंक जुटाने वालों को राज्य टीम में जगह दी जाएगी। ये खिलाड़ी झारखंड में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। भाग लेने वाले खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है और उनका टिकट भी कंफर्म कर लिया गया है। तीरंदाजों का पहला जत्था 15 दिसंबर को सुबह 7 बजे दानापुर एक्सप्रेस से टाटा नगर के लिए रवाना होंगे और वापसी 19 दिसंबर को होगी। दूसरा जत्था 16 दिसंबर को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से रवाना होगा और उनकी वापसी दानापुर एक्सप्रेस से 21 दिसंबर को होगी। कम्पाउन्ड कोच के रुप में कौन जाएगा इसकी घोषणा जल्द की जाएगी।

आयुष ने बताया कि रिकरव और कंपाउंड वर्ग के प्रतियोगिता में जो भी तीरंदाज राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाएगा उसने पुरस्कार के रुप में छत्तीसगढ़ आर्चरी एसोसिएशन द्वारा 25,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

प्रदेश में होगी एकलव्य विद्यालयों की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता

नई दिल्ली स्थित जनजातीय कार्य मंत्रालय के राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की चतुर्थ राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के सफल संचालन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी के चयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इसके लिए भारतीय खेल प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इम्पेनल्ड एजेंसियों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। प्री-बिड का बैठक 27 नवंबर 2024 और प्रेजेंटेशन 29 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे होगा। 02 दिसंबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक दस्तावेज़ जमा कर सकेंगे और 02 दिसंबर 2024 को शाम 5 बजे वित्तीय निविदा खोला जाएगा।

धान बेचकर किसानों के चेहरे में रौनक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी महा अभियान जारी है। धान बेचकर किसानों के चेहरे में रौनक दिख रहा है। किसानों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी के लिए धन्यवाद ज्ञापित किए हैं। धान खरीदी अभियान के इसी कड़ी में बलरामपुर जिला के ग्राम संतोषीनगर के किसान श्री अशोक सरकार ने बताया कि इस वर्ष 01 एकड़ खेत में धान का फसल लगाया था। उन्होंने पिछले सप्ताह धान बेचने के लिए टोकन लिया था। जिसके तहत आज वे अपना 45 बोरी धान बेचने समिति में आये हैं। किसान अशोक ने सुगमतापूर्वक धान खरीदी के राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है।

किसान श्री अशोक सरकार ने कहा कि शासन द्वारा धान खरीदी के लिए बनाई गई नीति से किसानों का मान बढ़ा है। किसान बिना किसी परेशानी के धान विक्रय कर पा रहे है। इसी प्रकार ग्राम संतोषीनगर के ही कृषक श्री विष्णु मण्डल बताया कि इस वर्ष वे 105 बोरी धान बेचने के लिए टोकन कटवाया है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा 31 सौ रुपए की दर से 21 क्विंटल धान की खरीदी होने से किसानों को बहुत संबल मिला है। उन्हें धान विक्रय करने में कोई परेशानी नहीं हुई। प्रशासन द्वारा उपार्जन केन्द्रों में किसानों के लिए शेड-पानी आदि आवश्यक समुचित व्यवस्था की गई है।

राज्य में अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी चिन्ह लगाना अनिवार्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर वाहन स्वामी द्वारा 120 दिवस के भीतर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा दो वेंडर क्रमशः मेसर्स रीयल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को निर्धारित दर पर एचएसआरपी चिन्ह लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।

परिवहन आयुक्त श्री एस. प्रकाश की अध्यक्षता में महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित बैठक में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर, उक्त परिवहन आयुक्त श्री मनोज ध्रुव, उप परिवहन आयुक्त सुश्री युगेश्वरी वर्मा, एआरटीओ श्री वाय.व्ही. श्रीनिवास, वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री अमित देवांगन, एन.आई.सी कंपनी प्रतिनिधि श्री मुकेश मल्होत्रा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमि., श्री विश्वजीत मुखर्जी, डायरेक्टर मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमि., श्री कौशल नियाज एवं अनुराग चौधरी उपस्थित थे।

परिवहन विभाग द्वारा समस्त आरटीओ कार्यालयों को जोन-ए और जोन-बी में बांटा गया है। जोन-ए के अंतर्गत शामिल आरटीओ कार्यालयों में अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों में एचएसआरपी चिन्ह लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड को दी गई है। जोन-ए के अंतर्गत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोण्डागांव, मुंगेली, बेमेतरा, कवर्धा, केरबा, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर एवं रायपुर आरटीओ कार्यालय शामिल हैं। इसी तरह जोन-बी के अंतर्गत आरटीओ कार्यालय रायगढ़, गरियाबंद, जशपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, दंतेवाड़ा, कांकेर, अम्बिकापुर, बैकुण्ठपुर, जदलपुर में पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी चिन्ह लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को सौंपी गई है। उक्त दोनों कम्पनियां निर्धारित दर पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाएंगी।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बालोद संभाग, बालोद

// निविदा आमंत्रण सूचना //

क्रमांक- 5822 / व.ले.लि./NIT- 07/2024-25/ बालोद, दिनांक 22/11/2024

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :-29/11/2024 अपरान्ह 5.30 बजे तक
ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदायें प्राप्त करने की अंतिम तिथि :-06/12/2024 अपरान्ह 5.30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि :- 09/12/2024 पूर्वान्ह 11.30 बजे तक

एनआईटी क्र. निविदा क्र.	कार्यका नाम / NoOfCalls	कार्य की अनुमानित लागत (रु.लाख में) अमानत राशि बैंक साल्वेंसी
1	2	3
07 T0041	अनुविभाग गुण्डरदेही के अंतर्गत शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही में सायकल स्टैण्ड का कार्य	18.63 13995.00 279900.00
07 T0042	अनुविभाग गुण्डरदेही के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय भवन गुण्डरदेही के सामने डी.जी. शेड, मालखान रूम शेड, अधिवक्ता कक्ष शेड, लोक सेवा केन्द्र तथा कार पार्किंग निर्माण तथा न्यायिक अधिकारी हेतु पृथक से विश्राम कक्ष एवं महिला पक्षकारों हेतु पृथक से कक्ष निर्माण कार्य।	17.57 13178.00 263550.00

नियम व शर्तें:-
1) पंजीयन की छायाप्रति 2) पेन कार्ड की छायाप्रति 3) जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की छायाप्रति 4) श्रमिक पंजीयन / ई.पी.एफ. पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति (राजपत्रित अधिकारी / नोटरी द्वारा) 5) निविदाकारों की श्रेणी 'द' से 'अ' निविदा प्रपत्र की कीमत राशि रू. 750.00 एवं कार्य की अवधि टी-0033 हेतु '02 माह' एवं टी-0034 हेतु '03 माह' होगी। 5) निविदा प्रपत्र के साथ Annexure-1, Annexure-2 & Annexure-3 फार्म भरना अनिवार्य होगा नहीं भरे जाने पर आपका निविदा प्रपत्र निरस्त किया जावेगा। (प्रपत्र संलग्न)

जी-242504038/5

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. बालोद संभाग, बालोद

महाराष्ट्र-झारखंड में सियासी सूझबूझ मस्त, अहंकार पस्त

कमलेश पांडे

महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा की दो सीटों और विभिन्न दर्जनाधिक राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम चौंकाने वाले हैं। ये चुनाव परिणाम इस बात का स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि मतदाताओं ने जहां सियासी सूझबूझ को ग्रेस देते हुए मस्त कर दिया है, वहीं राजनैतिक अहंकार को पूरी तरह से पस्त करके जमीन पर ला दिया है। मतलब यह कि पारस्परिक सिरफुटौव्वल को सिरे से खारिज कर दिया है। दो टूक शब्दों में कहें तो मतदाताओं ने जहां महाराष्ट्र के भाजपा नेता व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सहयोगियों सहित और झारखंड के जेएमएम नेता व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साथियों सहित अपनी-अपनी सियासत को नए सिरे से आगे बढ़ाने का मौका दिया है। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एनसीपी शरद पवार के नेता शरद पवार/सुप्रिया सुले, शिवसेना यूटीबी के नेता उद्धव भाऊ ठाकरे, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव आदि को जोर का झटका धीरे से दिया है, क्योंकि इनके बीच समुचित सामंजस्य के अभाव को मतदाताओं ने समय रहते ही भांप लिया और इनकी उम्मीदों के विपरीत परिणाम दिया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस नेत्री व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लाज जनता ने बचा ली है। वहीं, पंजाब में आप-कांग्रेस की टक्कर एकबार फिर सामने आई है, जो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगी। वहीं, कांग्रेस नेत्री और वायनाड, केरल के लोकसभा उपचुनाव की प्रत्याशी प्रियंका गांधी को जीत देकर उनका राजनीतिक मार्ग प्रशस्त कर दिया है। जबकि महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस की शिकस्त और बीजेपी को बढ़त मिली है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र के शिवसेना नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा एनसीपी नेता व उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी अपने-अपने दल को तोड़ने के बावजूद अपनी-अपनी पार्टी की विरासत पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। उनके इस मिशन को पूरा करने में भाजपा नेता व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चमत्कारिक नेतृत्व के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। कुल मिलाकर एक ओर महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति (गठबंधन) को प्रचंड जीत मिली है, वहीं दूसरी ओर झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली है। अब इनका मुख्यमंत्री कौन होगा और उनका मंत्रिमंडल कैसा होगा, इसको लेकर माथापच्ची शुरू हो चुकी है। वहीं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूटीबी के महाविकास अगाड़ी के अलावा यूपी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बिहार विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के निराशाजनक प्रदर्शन से इनकी आंतरिक रस्साकशी का भी भंडाफोड़ हो चुका है। इससे इनके लोकसभा चुनावों के संयुक्त प्रदर्शन पर भी पानी फिर गया है। इससे सेक्यूलर मतदाताओं में भी गहरी निराशा छा गई है। हालांकि, झारखंड में कांग्रेस और राजद को मिली जीत से पार्टी के नेतृत्व को थोड़ी राहत मिली है। वहीं, एनडीए की जोरदार सफलता से विकास, हिंदुत्व व राष्ट्रवाद की भावना एक बार फिर उफान पर है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे और पीएम नरेंद्र मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारों का असर महाराष्ट्र से लेकर यूपी-बिहार तक दिखाई पड़ा है। राजस्थान, मध्यप्रदेश से लेकर असम तक इसका असर पड़ा है। लेकिन झारखंड में यह नारा कैसे मिस्फायर कर गया, यह शोध का विषय है। वहीं, बंगलादेशियों/रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा भी यहां फेल हो गया, क्योंकि इनलोगों ने गोलबंद होकर इंडिया गठबंधन को पोल कर दिया। वहीं, लाडली बहना योजना की सफलता ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार को फिर से वहां लौटने का मौका दिया है। वहीं, केरल और कर्नाटक में कांग्रेस की सियासी इज्जत बच गई है। इसके अलावा वायनाड सीट के रिजल्ट को लेकर भी काफी उत्सुकता थी, जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा ने जीत हासिल की है।

संभल की घटना से उपजे जटिल सवाल

ललित गर्ग

यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं त्रासद है कि उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर एक सम्प्रदाय विशेष के लोगों ने जो हिंसा, नफरत एवं द्वेष को हथियार बनाकर अशांति फैलायी, वह भारत की एकता, अखण्डता एवं भाईचारे की संस्कृति को क्षति पहुंचाने का माध्यम बनी है। स्थानीय अदालत के आदेश पर एक मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा एवं उन्माद का भड़क उठना और इसके चलते तीन लोगों की जान चले जाना, चुनौतीपूर्ण, विडम्बनापूर्ण एवं शर्मनाक है। इस घटना में कई अन्य लोग घायल भी हुए, जिनमें 30 से अधिक पुलिसकर्मी भी हैं। इस हिंसा को टाला जा सकता था यदि अदालत के आदेश पर हो रहे सर्वेक्षण का हिंसक विरोध नहीं किया जाता।

ध्यान रहे कि जब ऐसा होता है तो बैर बढ़ने के साथ देश की छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। नि:संदेह इस सम्प्रदाय विशेष को भी यह समझने की आवश्यकता है कि जब देश कई चुनौतियों से दो-चार है, तब राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव को बल देना सबकी पहली और साझी प्राथमिकता बननी चाहिए। एक उन्मादी, विभाजित और वैमनस्यग्रस्त समाज न तो अपना भला कर सकता है और न ही देश को आगे ले जा सकता है। समय आ गया है कि उन मूल कारणों पर विचार किया जाए, जिनके चलते साम्प्रदायिक तनाव, नफरत एवं द्वेष बढ़ाने वाली घटनाएं थम नहीं रही हैं।

संभल की स्थानीय अदालत ने उस याचिका पर जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि मुगल बादशाह बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण एक मंदिर के स्थान पर किया था। स्थानीय अदालत के आदेश पर इसी मंगलवार को जब प्रारंभिक सर्वे किया गया था तब भी इलाके में तनाव फैला था, लेकिन उसे दूर कर लिया गया था। समझना कठिन है कि गत दिवस सर्वे के दौरान ऐसे प्रयास क्यों नहीं किए गए जिससे किसी तरह की अव्यवस्था और अशांति न फैलने पाए। रविवार को सर्वे के दौरान जिस तरह पुलिस पर पथराव किया गया और वाहनों में तोड़फोड़ करने के साथ उन्हें आग के हवाले किया गया, उससे लगता है कि कुछ उन्मादी तत्वों ने उपद्रव की तैयारी कर रखी थी। ऐसी घटनाएं सामाजिक तानेबाने को

क्षति पहुंचाने के साथ कानून एवं व्यवस्था के समक्ष चुनौती भी खड़ी करती हैं। यह चिंता की बात है कि यह एक चलन सा बनता जा रहा है कि जब सार्वजनिक स्थलों पर कोई धार्मिक आयोजन होता है, किसी अदालती आदेश पर जांच कार्य होता है तो प्राय: पहले किसी बात को लेकर विवाद होता है और फिर हिंसा शुरू हो जाती है। कई बार तो यह हिंसा बड़े पैमाने पर और किसी सुनियोजित साजिश के तहत होती दिखती है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई भीषण हिंसा यही संकेत करती है कि उसे लेकर पूरी तैयारी की गई थी।

संभल की ताजा घटनाओं के मूल में भड़काऊ नारे एवं संकीर्ण धार्मिकता के मनसूंबे सामने आये हैं। इस तरह की घटनाओं का बार-बार होना अच्छा नहीं है, मंदिर-मस्जिद के एक और मामले ने तनाव की स्थिति उत्पन्न करके शांति एवं सौहार्द को खण्डित किया। यदि मस्जिद पक्ष का यह मानना है कि जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश सही नहीं तो उसे ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। अदालत के आदेश की अवहेलना करने के लिए हिंसा का सहारा लेने का कहीं कोई औचित्य नहीं और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब निचली अदालत के किसी फैसले के खिलाफ ऊंची अदालतों में जाने का रास्ता खुला हो। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या कुछ राजनीतिक दल एवं सम्प्रदाय विशेष के लोग किसी भी बहाने भड़कने और हिंसा करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं? वास्तव में जैसे यह एक सवाल है कि क्या भारतीय संस्कृति के अस्तित्व एवं अस्मिता से जुड़े इन धार्मिक स्थलों के नाम पर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी करना जरूरी समझ लिया गया है? इन प्रश्नों पर संकीर्ण धार्मिकता से परे होकर गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए। इसी तरह पुलिस प्रशासन को भी यह देखना होगा कि वैमनस्य बढ़ाने वाली घटनाएं क्यों बढ़ती चली जा रही हैं?

यह सही है कि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम किसी धार्मिक स्थल में बदलाव का निषेध करता है, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह अधिनियम ऐसे किसी स्थल के सर्वेक्षण की अनुमति भी प्रदान करता है और इसी कारण वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण हुआ और धार में भोजशाला परिसर का भी। मथुरा में ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। मंदिर-मस्जिद के विवाद नए नहीं हैं। इन विवादों को सुलझाने की आवश्यकता है। इसका एक तरीका न्यायपालिका का सहारा लेना है और दूसरा आपसी सहमति से विवाद को हल करना। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि जहां भी ऐसे विवाद हैं, उन्हें दोनों समुदाय आपस में मिल-बैठकर हल करें। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि समाज में सद्भाव, सौहार्द एवं शांति बनी रहेगी। यह समझा जाना चाहिए कि इन दोनों उपायों के अतिरिक्त हिंसा एवं नफरत कोई उपाय नहीं है। इसी के साथ यह भी समझना होगा कि देश को अतीत से अधिक भविष्य की ओर देखने और मंदिर-मस्जिद विवादों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। इससे इन्कार नहीं कि विदेशी आक्रमणकारियों ने अनगिनत मंदिरों का ध्वंस किया। अतीत में हुए इन ज्यादतियों, अत्याचारों एवं विध्वंस घटनाक्रमों को सुधारने की संभावनाएं किसी भी दृष्टि से गलत नहीं कही जा सकती।

देश का चरित्र बनाना है तथा स्वस्थ, सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण समाज की रचना करनी है तो हमें एक ऐसी आचार संहिता को स्वीकार करना होगा जो जीवन में पवित्रता दे। राष्ट्रीय प्रेम व स्वस्थ समाज की रचना की दृष्टि दे एवं कदाचार-संकीर्णता-कट्टरता के इस अंधेरे कुएँ से निकाले। बिना इसके देश का विकास और भौतिक उपलब्धियां बेमानी हैं। व्यक्ति, परिवार और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इरादों की शुद्धता महत्व रखती है, जबकि हमने इसका राजनीतिकरण कर परिणाम को महत्व दे दिया। घटिया उत्पादन के पर्याय के रूप में जाना जाने वाला जापान आज अपनी जीवन शैली को बदल कर उत्कृष्ट उत्पादन का प्रतीक बन विश्वविख्यात हो गया। यह राष्ट्रीय जीवन शैली की पवित्रता का प्रतीक है। इसी तरह भारत भी आज विश्वविख्यात होने की दिशा में अग्रसर हो रहा है, तो उसकी बढ़ती साख एवं समझ को खण्डित करने वाली शक्तियों को सावधान करना ही होगा। भारत जैसी माटी में जन्म लेना बड़ी मुश्किल से मिलता है। विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुम्बकम की विचारधारा वाला यह राष्ट्र विभिन्न संस्कृतियों एवं सम्प्रदायों को अपने में समेटे है तो यह यहां के बहुसंख्यक समुदाय की उदार सोच का ही परिणाम रहा है, इसी बहुसंख्यक हिन्दू समुदाय को आखिर कब तक कमजोर किया जाता रहेगा? क्यों किया जायेगा? कल पर कुछ मत छोड़िए। कल जो बीत गया और कल जो आने वाला है- दोनों ही हमारी पीठ के समान हैं, जिसे हम देख नहीं सकते। आज हमारी हथेली है, जिसकी रेखाओं को हम देख सकते हैं। अब हथेली की रेखाओं को कमजोर करने एवं उसे लहूलुहान होते हुए नहीं देखा जा सकता?

एक सम्प्रदाय विशेष के हिंसक हमलों ने आज तेजी के साथ हिंसा, असहिष्णुता, नफरत, बिखराव और घृणा की साम्प्रदायिक जीवन शैली का रूप ग्रहण कर लिया है। यह खतरनाक स्थिति है, कारण सबको अपनी-अपनी पहचान समाप्त होने का खतरा दिख रहा है। भारत मुस्लिम सम्प्रदायवाद से आतंकित रहा है। आवश्यकता है धर्म को प्रतिष्ठापित करने के बहाने राजनीति का खेल न खेला जाए। धर्म और सम्प्रदाय के भेद को गड्मड् न करें। धर्म सम्प्रदाय से ऊपर है। धर्म में धार्मिकता आये, कट्टरता न आये। राजनीति में सम्प्रदाय न आये, नैतिकता आए, आदर्श आए, श्रेष्ठ मूल्य आएँ, सहिष्णुता आये, सह-अस्तित्व के प्राचीन मूल्य एवं जीवनशैली आये। अत: सम्प्रदायवाद से ऊपर उठकर सार्वभौम धर्म का साक्षात्कार ही हममें नवीन आत्मविश्वास, सशक्त भारत-विकसित भारत का संचार करेगा। उपनिषदों में कहा गया है कि सभी मनुष्य सुखी हों, सभी भयमुक्त हों, सभी एक-दूसरे को भाई समान समझें। यह भारतीय धर्म चिन्तन का निचोड़ है और यही हिन्दू धर्म का निचोड़ है। जहां विश्व एक ही नीड़-सा लगे। भारत में हिन्दू-मुस्लिम हित परस्पर टकरा रहे हैं, इसलिए साम्प्रदायिकता बढ़ रही है। धार्मिकता नष्ट हो रही है। साम्प्रदायिकता का जन्म अनेक जटिल तत्वों से जुड़ा है- आर्थिक, धार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक। इसमें मनोवैज्ञानिक ज्यादा महत्वपूर्ण है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदपुराण-परम्पराध्याय:

गतांक से आगे...

यदि उक्त ग्रन्थों से सर्गादिक-प्रतिपादक वाक्यों का उद्धरण देकर उन्हें पुराण कहने की दुश्चेष्टा की जाए तो इस तरह के सैकड़ों मन्त्र मन्त्रभाग में भी विद्यमान हैं। अत: सर्गादि पञ्चलक्षण अव्याप्त होने के कारण ब्राहाण भाग पुराण नहीं हो सकता।

(3) सर्वत्र शास्त्रों में पुराणों के नाम ब्राह्म, पाद्म, वैष्णव ही लिखे हैं, परन्तु ब्राह्मग्रन्थों में उक्त नामों वाला कोई भी ग्रन्थ नहीं है। अत: वे पुराण नहीं हो सकते।

(4) पुराणों की संख्या सर्वविदित अठारह है, परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों की इयत्ता का कहीं भी उल्लेख नहीं तथा याज्ञिक विषयविभाग के अनुसार उन्हें विभक्त किया जाए तो वे भी चतु: संहिताओं की तरह चार प्रकार के ही प्रतीत होते हैं। अत: संख्या-रूप लक्षण के अव्याप्त होने से भी ब्राह्मणग्रन्थ पुराण नहीं हो सकते।

(5) प्राय: सभी ऋषियों ने वेदों की 1131 शाखायें मानी हैं। प्रतिवादियों के दादागुरु स्वामी दयानन्द जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि ग्रन्थों में कहीं 1127 और कहीं 1131 शाखाओं का उल्लेख किया है। सो जिस प्रकार उपलब्ध चारों संहिताएँ क्रमश:- शाकल, माध्यंदिनी, कौथुमी और शौनिकी नामक शाखाएँ हैं इसी प्रकार उपलब्ध ब्राह्मण, उपनिषद् आदि भी वेदशाखाओं के ही ग्रन्थ विशेष हैं। यदि चार शाखाएँ मान्य हो सकती हैं तो शेष भी उसी भान्ति मान्य होनी चाहियें। अत: ब्राह्मणग्रन्थ वेद शाखा होने के कारण पुराण नहीं हो सकते।

(6) पूर्व भीमांसादर्शन में मन्त्रभाग की तरह ब्राह्मणभाग की भी अपौरुषयता सिद्ध की है, अत: दोनों का वेदत्व भी तुल्य है। फिर वेदभूत ब्राह्मणों को पुराण कैसे कहा जा सकता है ?

क्रमश: ...

वशिष्ठ-विश्वामित्र कैसे बने शत्रु? कालांतर में कठोर तप से ब्रह्मर्षि बने कौशिक

आशुतोष गर्ग

एक बार गंधर्वराज चित्ररथ की अर्जुन से भेंट हुई, तो उन्होंने अर्जुन को वशिष्ठ की महिमा सुनाते हुए कहा, 'वशिष्ठ ने अपनी तपस्या के बल पर काम और क्रोध पर विजय पाई थी। विश्वामित्र के अनेक अपराध करने पर भी वशिष्ठ के मन में क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ और वह हर बार विश्वामित्र को क्षमा करते गए। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पुत्रों तक का नाश कर दिया, फिर भी वशिष्ठ के मन में प्रतिशोध का भाव जागृत नहीं हुआ। वह चाहते तो अपने पुत्रों को जीवित कर सकते थे, पर उन्होंने यमराज के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था, इसीलिए उनका नाम वशिष्ठ पड़ा।'

अर्जुन ने चित्ररथ से कहा, 'वशिष्ठ और विश्वामित्र, दोनों सिद्ध तपस्वी थे, तो फिर

दोनों शत्रु कैसे हो गए?' अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में चित्ररथ ने कहा- 'प्राचीन समय में कान्यकुब्ज देश में गाधि नाम के एक बड़े यशस्वी राजा हुए। वह राजर्षि कुशिक के पुत्र थे। गाधि के पुत्र का नाम कौशिक था, जो राजकुल में जन्म लेने पर भी आगे चलकर महर्षि विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार राजा कौशिक शिकार खेलते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ ने विधिपूर्वक उनका स्वागत-सत्कार किया और अपनी नंदिनी नामक गाय के प्रताप से अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ आदि की व्यवस्था कर कौशिक को तृप्त कर दिया।

इस आतिथ्य से कौशिक बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने वशिष्ठ से कहा, 'मैं क्षत्रिय हूं और आप ब्राह्मण। आप तपस्या-स्वाध्याय में लीन रहते हैं। आपको इस गाय की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, किंतु मैं राजा हूं। यदि यह मेरे पास होगी, तो इसके माध्यम से राज्य और प्रजा, दोनों समृद्ध हो जाएंगे। अत: आप मुझसे एक अर्बुद गायें ले लीजिए, परंतु अपनी नंदिनी गाय मुझे दे दीजिए।' वशिष्ठ बोले, 'मैंने यह गाय देवता, अतिथि, पितर और यक्षों की सेवा के लिए रखी हुई है। मैं किसी भी मूल्य पर यह गाय आपको नहीं दे सकता।'

कौशिक ने तर्क दिया, 'आप राजा की इच्छा का अनादर कर रहे हैं। यदि आप खुद मुझे यह गाय नहीं देंगे, तो मैं बलपूर्वक इसे ले जाऊंगा।' इस पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, 'आप बलवान क्षत्रिय हैं, जो चाहे कर सकते हैं। फिर सोच-विचार कैसा?' यह सुनकर कौशिक ने नंदिनी को जबर्दस्ती ले जाने का प्रयास किया, तो वह डकराती हुई वशिष्ठ के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, 'ऋषिवर! राजा के सैनिक मुझे चाबुक और डंडों से पीट रहे हैं, मैं अनाथ की तरह डकरा रही हूं। आप मेरी सहायता क्यों नहीं करते?' नंदिनी का करुण-क्रंदन सुनकर वशिष्ठ क्षुब्ध नहीं हुए। नंदिनी बोली, 'यदि आपने मुझे नहीं छोड़ा है, तो मुझे बलपूर्वक कोई नहीं ले जा सकता।' यह कहकर नंदिनी ने सिर ऊपर उठा लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका भीषण रूप देखकर कौशिक के सैनिक इधर-उधर भागने लगे। कालांतर में कौशिक ने कठोर तप करके राजर्षि, महर्षि और अंत में ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की और विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस बीच विश्वामित्र कई बार वशिष्ठ से पराजित हुए। यही कारण था कि वशिष्ठ और विश्वामित्र का परस्पर वैर हो गया।

क्या ट्रंप-मोदी की 'दोस्ती' रंग लाएगी?

पी. चिदंबरम

डोनाल्ड ट्रंप अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने हैं। इसमें अभी सात सप्ताह का समय बचा है, लेकिन दुनियाभर में यह विषय चर्चा में है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का हमारे देश, हमारे शहर, हमारी नौकरी या दुनिया की हर चीज पर क्या असर होगा। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बाजार सूचकांकों में गिरावट आ रही है। 5 नवंबर को सेंसेक्स 78,782 पर बंद हुआ, तब डॉलर की दर 84.11 रुपये थी। जब मैं यह कॉलम लिख रहा था, उसके एक दिन पहले सेंसेक्स 77,156 पर बंद हुआ और डॉलर विनिमय दर 84.50 रुपये थी।

अब डोनाल्ड ट्रंप की मूल मान्यताओं पर नजर डालते हैं। हम जानते हैं कि वह एक व्यापारिक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं और उनका मानना है कि उच्च टैरिफ या दर ही अमेरिकी हितों की रक्षा कर सकती है। उन्होंने खासकर चीन से आयातित सामानों पर उच्च शुल्क लगाने की बात की है। बाइडन के शासनकाल में चीन के साथ अमेरिका का व्यापारिक घाटा 2021 में 352 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 382 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2022), 279 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2023) और 217 बिलियन अमेरिकी डॉलर (सितंबर 2024 तक) रहा है। अमेरिका की अधिकांश आबादी को बड़ी मात्रा में चीन के माल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी की आवश्यकता है। अगर उन सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिया जाता है तो अमेरिका के लोगों और उद्योगों की लागत बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में यूएस फेड नीतिगत ब्याज दर में वृद्धि करेगा, जिसमें उसने इस साल दो बार कटौती की थी।

दूसरी तरफ, चीन को अपने यहां रोजगार बनाए रखने के लिए वस्तुओं का उत्पादन जारी रखना होगा। अगर अमेरिका, चीन के सामानों पर टैरिफ बढ़ाता है तो वह दूसरे देशों में अपना माल 'डंप' करेगा। भारत में पहले से ही चीनी सामानों पर सबसे ज्यादा एंटी-डंपिंग शुल्क है। ऐसे में उच्च अमेरिकी टैरिफ बदले की भावना को पैदा कर सकते हैं,

जिसका परिणाम विश्व व्यापार को भुगतना पड़ सकता है।

अमेरिका में कुछ लोग राजकोषीय घाटे के बारे में उसी तरह बातें करते हैं, जिस तरह भारत और अन्य देश राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के बारे में चिंतित हैं। इसका कारण यह है कि अमेरिका अपने घाटे को आसानी से पूरा कर लेता है, क्योंकि चीन समेत दूसरे देश अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते हैं। अमेरिका के कुल राष्ट्रीय ऋण 21,000 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से चीन का हिस्सा लगभग 1170 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। लेकिन अगर अमेरिका का राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो जाहिर है कि महंगाई बढ़ेगी। नतीजे के तौर पर उच्च ब्याज दरें पूंजी के प्रवाह को बिल्कुल उलट देंगी, जिसकी वजह से भारत जैसे विकासशील देशों से धन लगातार बाहर जाएगा। मजबूत डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्य घट जाएगा।

ट्रंप ने अमेरिका में कारखानों को वापस लाने का वादा किया है। वह अमेरिकी उद्योगों को अपने कारखाने स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दे सकते हैं। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी आएगी। अगर अमेरिकी व्यवसायी तब भी विदेश में अपने कारखाने स्थापित करना चाहें तो ट्रंप प्रौद्योगिकी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ट्रंप ने पहले भी भारत पर अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाने और 'मुद्रा में हेरफेर करने वाला' होने का आरोप लगाया है। क्या ट्रंप और मोदी के बीच की 'दोस्ती' भारत के प्रति ट्रंप के रवैये को नरम करेगी और यह भारत के लिए एक अपवाद बन पाएगी, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा कथित 'अवैध' आप्रवासन है। ट्रंप इसके लिए बेरोजगारी से लेकर अपराध और नशीली दवाओं तक सभी को दोषी मानते हैं। ट्रंप ने पहले 100 दिनों में दस लाख अवैध अप्रवासियों को बाहर करने का वादा किया है।

इस प्रक्रिया में कितने भारतीयों को निर्वासित किया जाएगा, यह तो अभी मालूम नहीं है, लेकिन कुछ तो निर्वासित किए ही जाएंगे। इसका असर भारत-अमेरिका संबंधों पर भी पड़ेगा। ट्रंप एच1बी1 वीजा हासिल करने के नियमों को और सख्त कर सकते हैं। हालांकि अमेरिकी उद्योग, विश्वविद्यालय और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अधिक योग्य भारतवासियों को अपने यहां फिर से बसाकर उन्हें अमेरिकी नागरिक बनाना चाहेगी। यदि ट्रंप और अमेरिकी नियोक्ता अपनी-अपनी बातों पर अडिग रहते हैं तो यह एक अपरिवर्तनीय शक्ति द्वारा अचल अवरोध को पूरा करने का मामला होगा।

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद तेल और दवा उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। गौर करने वाली बात है कि ट्रंप ने उस क्रिस राइट को ऊर्जा सचिव के रूप में नामित किया है, जो फ्रैकिंग और ड्रिलिंग के प्रबल समर्थक हैं। वह इस बात से ही इनकार करते हैं कि दुनिया में जलवायु संकट है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन पर होने वाली सीओपी (कॉप) वार्ता विफल तो नहीं होगी, लेकिन इसे गंभीर झटका जरूर लग सकता है। भारत वर्तमान में सीओपी के प्रयास का समर्थन तो करता है, लेकिन वह चाहता है कि इसकी गति धीमी हो और ऐसा हो सकता है। फार्मास्युटिकल मोर्चे पर, कम विनियमन और ऊंची कीमतों की उम्मीद में अमेरिका में फार्मा शेयरों में तेजी आई है। दुनियाभर में दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी और स्वास्थ्य सेवा को सार्वभौमिक बनाने के हमारे प्रयास पर असर पड़ेगा।

अंत में यह देखना होगा कि उन दो युद्धों के प्रति ट्रंप का रवैया क्या होगा, जिसमें हर दिन दर्जनों निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। स्कूलों और अस्पतालों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहे हैं? ट्रंप ने 'युद्ध रोकने' का वादा तो किया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया है कि वह क्या करेंगे। उनके पिछले रिकॉर्ड और घोषणाओं से संकेत मिलता है कि वह इस्राइल का समर्थन करेंगे। वह यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर रूस के साथ समझौता करने के लिए दबाव डाल सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी में उठाए गए कदम के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि युद्ध समाप्त हो जाएगा और स्थायी शांति स्थापित हो जाएगी। इसके विपरीत यह भी हो सकता है कि यदि युद्ध तेज हो गए तो आपूर्ति श्रृंखलाएं और बाधित हो जाएंगी, जिसका विकासशील देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

डोनाल्ड ट्रंप के 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' से पूरी दुनिया को बेहतर, सुरक्षित या अधिक समृद्ध स्थान बनाने की संभावना नहीं है। ट्रंप के अनुसार, यह अमेरिका के लिए फायदेमंद है। अमेरिकी चुनाव के नतीजों ने भी इस बात को साबित कर दिया, जो कि ट्रंप के हित में भी है।

आज का इतिहास

1966 उरुग्वे ने संविधान अपनाया।
1971 सोवियत रूस के मार्स ऑर्बिटर द्वारा मंगल ग्रह पर उतारा गया।
1975 ब्रिटेन की सरकार ने स्कॉटलैंड और वेल्स दोनों को आंशिक स्व-शासन देने का फैसला किया। हालांकि, स्कॉटलैंड ब्रिटेन की एकता को कम करने के लिए किसी भी कार्रवाई का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने वाला था।
1975 गिनीज़ बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स के सह-संस्थापक रॉस मैक्किर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
1978 कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जो एक स्वायत्त कुर्द राज्य के गठन पर तुर्की के साथ संघर्ष में थी, की स्थापना की गई थी।
1978 सैन फ्रांसिस्को के मेयर जॉर्ज मॉस्कॉन और खुले तौर पर समलैंगिक पर्यवेक्षक हार्वे मिल्क की हत्या सुपरवाइजर डैन व्हाइट ने की थी।
1982 यासुहिरो नकासन जापान के प्रधान मंत्री बने।
1983 मिसाइल शिपमेंट इटली पहुंचे। इतालवी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन सैन्य हथियारों को बहुत जल्द रणनीतिक रूप से रखा जाना था। आश्चर्यजनक रूप से कुछ समूहों के लिए, युद्ध-विरोधी ताकतों ने अभी तक इस मिसाइल तैनाती की प्रतिक्रिया में प्रदर्शन नहीं किया था।
1983 स्पेन के मैड्रिड शहर में बारजस एयरपोर्ट के पास कोलंबिया की एविएनेका फ्लाइट 11 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 192 लोगों में से 181 की मौत हो गई।
1999 सेंटर-लेफ्ट न्यूज़ीलैंड लेबर पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाली हेलेन क्लार्क न्यूज़ीलैंड के इतिहास में पहली चुनी गई महिला प्रधानमंत्री बनीं, जो लेबर और अलायंस पार्टी के सदस्यों की गठबंधन सरकार की कमान संभाल रही थीं।
1999 लेबर पार्टी ने न्यूज़ीलैंड के आम चुनाव में गवर्निंग नेशनल पार्टी को हराया, जिससे लाबोर की हेलेन क्लार्क चुनाव में प्रधानमंत्री का पद जीतने वाली पहली महिला बनीं।
1999 हेलेन क्लार्क न्यूज़ीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं।
2001 हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक्सट्रासोलर ग्रह एचडी 209458 बी के वायुमंडल में सोडियम का पता लगाया, जो कि हमारे सौर मंडल के पहले ग्रहों का वायुमंडलीय माप है।
2002 राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू। बुश के आदेश के पहले दिन, अमेरिकी सरकार आतंकवादियों के लिए धन के प्रवाह को रोकने के लिए काम कर रही थी। यह एक विश्वव्यापी आधार पर लागू किया जा रहा था-विशेष रूप से सऊदी अरब में।
2005 डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी लिम किट सियांग के नेता ने मलेशियाई कैदी दुर्व्यवहार कांड में अपने कार्यों के लिए मलेशियाई पुलिस उपमहानिरीक्षक के इस्तीफे की मांग की।

झारखंड विधानसभा चुनाव : भाजपा का दांव पूरी तरह फेल हो गया

चेतनादित्य आलोक

झारखंड विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों को धता बताते हुए झामुमो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। बता दें कि इस बार के झारखंड के चुनाव में आइएनडीआइए (इंडिया) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) गठबंधनों के बीच सीधी और जबर्दस्त टक्कर हुई। कांटे की इस टक्कर में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली 'इंडिया' गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से सबसे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) कुल 34 सीटें जीत कर सबसे आगे रही। वहीं, कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने 04 और कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट लिबरेशन) यानी सीपीआई (एमएलएल) ने 02 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार देखा जाए तो इंडिया गठबंधन ने राज्य की कुल 81 में से 56 सीटें प्राप्त कर न केवल अपनी सरकार बचा ली है, बल्कि जबर्दस्त वापसी की है। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन को झारखंड चुनाव में एक बार फिर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बता दें कि एनडीए गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू), जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और लोकतांत्रिक जनता पार्टी (लोजपा) रामविलास ने एक-एक सीटों पर जीत दर्ज करने में सफलता पाई है। तात्पर्य यह कि झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 24 सीटें मिली हैं।

इससे पहले एग्जिट पोल में राज्य में बीजेपी और उसकी अगुवाई वाले एनडीए को स्पष्ट तौर पर विजेता के रूप में दिखाया जा रहा था, लेकिन परिणाम बताते हैं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन ने राज्य की जनता को अपने वादों और दावों के प्रति लुभाने में सफलता प्राप्त करते हुए बंपर जीत हासिल की। वहीं, दूसरी ओर बीजेपी अपनी सारी ताकत झोंकने के बाद भी आदिवासियों समेत राज्य की जनता को इंप्रेस नहीं कर पाई। बता दें कि भाजपा ने झारखंड में चुनावों से पहले 'लव जिहाद' तथा 'लैंड जिहाद' का मुद्दा बेहद जोर-शोर से उठाया था। गौरतलब है कि भाजपा की ओर से की गई हिंदू और मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश के बीच हेमंत सोरेन बिल्कुल शांत और उकसाने वाले बयानों से बचते दिखे। यह निश्चित रूप से हेमंत सोरेन की राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। हालांकि, उनकी ही पार्टी के कुछ नेता और इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों के कई नेता कई मौके पर लगातार हिंदू-मुसलमान करते अवश्य देखे और सुने गए। इस प्रकार, राज्य में पूरे चुनावी काल में हिंदू-मुसलमान के नाम पर विष-वमन होता रहा।

इन सबके बीच भाजपा का एजेंडा झारखंड में पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दिया, जबकि भाजपा ने राज्य में चुनाव प्रचार में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने ही लाइव रैलियां कीं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से लेकर तमाम स्टार प्रचारकों ने कमान संभाल रखी थी। यहां तक कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा राज्य में दो महीने तक जमे रहे, जिन्होंने बांग्लादेश से 'घुसपैठियों' को आने देने के लिए सोरेन सरकार पर जोरदार हमले किए। गौरतलब है कि भाजपा ने अपनी रैलियों में झारखंड की 'माटी, बेटी और रोटी' का मुद्दा उठाया। इस मामले में भाजपा के नेताओं ने हेमंत सोरेन की सरकार पर आरोप लगाए कि राज्य में 'माटी, बेटी

और रोटी' खतरे में हैं। यहां तक कि पार्टी की ओर से जेएमएम के विरूद्ध ट्रंप कार्ड के तौर पर चंपई सोरेन और सीता सोरेन को इस्तेमाल करने की कोशिश भी की गई, लेकिन भाजपा का यह दांव भी नहीं चला। इस प्रकार देखा जाए तो झारखंड में भाजपा का 'माटी, बेटी और रोटी' तथा 'घुसपैठिया' का मुद्दा उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं चल पाया।

झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के भीतर कुछ नए और पुराने नेताओं को लेकर लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि राज्य के भावी मुख्यमंत्री के रूप में किसे नेतृत्व सौंपा जाए- नए, तेज-तर्रार और युवा नेता को अथवा पुराने, स्थापित और मजे हुए नेता को। ऐसा बताया जाता है कि पार्टी के भीतर कलह और मनमुटाव जारी रहने के कारण इस बात पर एक राय नहीं बन पाई कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले उसकी ओर से किस नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। यही कारण है कि बड़ी संख्या में राज्य की गैर-आदिवासी जनता ने भी उसे नकार दिया। बता दें कि किसी भी कार्य में अनिर्णय की स्थिति गलत या बुरे निर्णय से भी अधिक घातक मानी जाती है। राजनीति में तो यह बिल्कुल ही नहीं चलने वाली। इसलिए अब कम-से-कम भाजपा को इसे गंभीरता से लेना होगा और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इस बात पर प्राथमिकता से विचार करते हुए पार्टी की ओर से राज्य को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना ही होगा, अन्यथा पार्टी चाहे जितने भी प्रयास क्यों न कर ले, 2024 दोहराने के लिए राज्य की जनता हमेशा बाध्य होती रहेगी।

यह एक कड़वा सच है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऐसे प्रभावशाली चेहरे का बेहद आभाव है, जो जनता को प्रभावित कर अपनी ओर आकर्षित कर सके। जिस प्रकार, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी को विजयी बनाने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है और जिस प्रकार हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पार्टी के लिए एक जिम्मेदार चेहरा हैं, वैसे ही चुनाव से पहले झारखंड में भी पार्टी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में एक जिम्मेदार चेहरा पेश करना चाहिए था। गौरतलब है कि ऐसा नहीं करके भाजपा ने एक प्रकार से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, जबकि विपक्ष की ओर से तो पहले ही दिन से यह बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि यदि इंडिया गठबंधन ने चुनाव जीता तो उनकी ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन ही होंगे। हालांकि, ऐसा नहीं है कि भाजपा के भीतर ऐसे लोगों का अभाव है। गौर करें तो पार्टी के भीतर कई नेता हैं, जो हेमंत सोरेन को कड़ी टक्कर देने में सक्षम हैं। यहां तक कि कुछ नेता तो उनसे बेहतर परफॉरमेंस करने की क्षमता और कौशल भी रखते हैं, लेकिन पार्टी की ओर से उन्हें आगे नहीं करने के कारण चुनाव के दौरान मतदाताओं के बीच इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही कि एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा।

गौरतलब है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी को 8.36 एकड़ जमीन के अवैध कब्जे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। इसे मुद्दा बनाकर भाजपा ने चुनाव के दौरान झामुमो नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, किंतु यह हमला उस पर ही भारी पड़ गया। दरअसल, जब हेमंत सोरेन जेल में थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को पीड़ित (विक्टिम) कार्ड खेलने के लिए प्रेरित किया, जिसके पश्चात् कल्पना राज्य की आदिवासी जनता के बीच जाकर उनसे अपने विरूद्ध भाजपा शासन द्वारा साजिशें किए जाने की बात बताती रहीं। दूसरी ओर भाजपा इस भ्रम में बैठी रही कि उसकी रणनीति राज्य के विधानसभा चुनाव में सफल हो जाएगी। ऊपर से महत्वपूर्ण चुनावों से ठीक पहले हेमंत सोरेन को जेल से बेल पर छोड़ा जाना भाजपा की सेहत के लिए और घातक हो गया। चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी ने जम कर पीड़ित कार्ड खेला और अंततः राज्य के आदिवासियों को बहलाने-फुसलाने में सफल हुए। यही कारण है कि झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में इस बार मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड स्तर पर रहा। बता दें कि राज्य की 26 आरक्षित सीटों में से 21 सीटों पर जेएमएम प्रत्याशी विजयी हुए, जो यह दर्शाता है कि राज्य के आदिवासी मतदाताओं ने भाजपा को इस चुनाव में बुरी तरह से नकार दिया है।

विपक्ष का कमजोर होना क्या ठीक है लोकतंत्र के लिए?

राजेश बादल

यह सच है कि किसी भी लोकतंत्र में बहुमत पाने वाली पार्टी सत्ता पर काबिज होती है। लेकिन, यदि विजय एकतरफा हो तो वह जम्हूरियत के नजरिए से घातक भी होती है। अधिनायकवादी बीजों के अंकुरित होने का खतरा बना रहता है। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए हुए निर्वाचन का परिणाम कुछ ऐसा ही सन्देश देता है। कोई सरकार कितना ही अच्छा काम करे (जो कि उसका कर्तव्य है) मतदाताओं को उसे नियंत्रित करना ही होगा। किसी भी प्रजा तांत्रिक मुल्क में पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच स्वाभाविक संतुलन होना चाहिए। यदि सदन में पक्ष का आकार विराट और ट्रैक्टर के पहिए जैसा हो और प्रतिपक्ष का आकार दुर्बल और साइकल के पहिए की तरह हो तो लोकतंत्र की गाड़ी रफ्तार नहीं पकड़ सकती। यह ठीक वैसा ही होगा कि एक मरियल और निर्बल इंसान रिंग में उतरकर किसी पहलवान को चुनौती दे। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी के खुद को तानाशाह समझने का खतरा विकराल हो जाता है। इसी बरस कांग्रेस की अगुआई वाले गठबंधन ने जब लोकसभा चुनाव में 234 सीटें जीती और दस साल से सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी को अपने बूते पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इससे पहले 2019 के निर्वाचन में सत्तारूढ़ पार्टी अपने दम पर बहुमत लेकर आई थी तो उसका व्यवहार विपक्ष के साथ उपेक्षा भरा था। प्रतिपक्ष इतना दीन-हीन और बौना था कि सरकार के पूरे कार्यकाल में दर्प और घमंड वाली शैली पनपी थी। संसद में प्रतिपक्ष को भरोसे में नहीं लिया गया। राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर चर्चा नहीं हुई और हिन्दुस्तान के सामने मुंह बाए खड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। चाहे वह मंहगाई हो या बेरोजगारी ,भ्रष्टाचार हो या लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण,सभी में प्रतिपक्ष का स्वर बेहद मद्धम था। यहां तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ही बयान दे दिया कि पार्टी को उस संगठन की जरूरत नहीं है। यह सत्तारूढ़ दल का अहं भाव ही था। भारत के मतदाता ने इसे ताड़ लिया था। इसी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम लोकतंत्र को संतुलित करते हुए आए थे। अब केंद्र सरकार बैसाखियों के सहारे है और प्रतिपक्ष मजबूत स्थिति में है तो भारतीय प्रजातंत्र संतोष कर सकता है। लेकिन महाराष्ट्र के हालिया परिणाम एक बार फिर यही अंदेशा उत्पन्न करते हैं। प्रतिपक्ष का क़द विधानसभा में अत्यंत नाटा है और वह सत्ताधारी पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं रहा है। विडंबना यह कि बीजेपी के सहयोगी दल भी उसकी विराट जीत से आशंकित दिखाई देते हैं।सवाल यह भी खड़ा होता है कि 132 विधायक चुनकर विधानसभा में भेजने वाली पार्टी अपना मुख्यमंत्री क्यों न बनाए? क्या वह शिंदे को एक बार फिर स्वीकार करे ? जबकि शिंदे के पास बीजेपी के दावे को चुनौती देने वाला आंकड़ा नहीं है, हालांकि बिहार की तर्ज पर बीजेपी ऐसा कर सकती है ,पर यह भी हक़ीक़त है कि शिंदे ,नीतीश कुमार नहीं हैं। वैसे भी नीतीश कुमार अपनी कीकड़ बदन वाली पार्टी के साथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं और बड़े आकार वाली बीजेपी वहां अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी तो यह मान्य लोकतान्त्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। यदि शिंदे को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर वे बीजेपी से उपकृत भाव के साथ काम करेंगे और महाराष्ट्र के लिए यह बेहतर स्थिति नहीं होगी। प्रत्येक सभ्य लोकतंत्र पक्ष और प्रतिपक्ष के एक सम्मानजनक आकार को पसंद करता है।कामयाबी शिखर को छूने वाली हो तो फिर ढलान में उतरने के अलावा कुछ नहीं होता। शिखर के ऊपर कोई दूसरा शिखर नहीं होता।

महाराष्ट्र में पर्दे के पीछे से आरएसएस ने कैसे बदली तस्वीर

अभिनय आकाश

एक दो दिन पहले तक लग रहा था कि महाराष्ट्र की लड़ाई बहुत नजदीक होगी। वहीं एक दो हफ्ते पहले तक तो लग रहा था कि प्रदेश में महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी। लेकिन 20 तारीख को वोटिंग के बाद कई सर्वे आए कभी महायुति को आगे दिखाया गया। लेकिन जब नतीजे आएं तो सभी की आंखें चकाचौंध से भर उठी। बीजेपी ने अभी तक महाराष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने ऐसा क्या किया है कि उसे प्रदेश में इतनी बड़ी ग्रोथ मिल गई है। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी और आरएसएस के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला। जिसका लाभ महायुति को इस बार के चुनाव में देखने को मिला। जानकारों का कहना है कि जिस तरह से इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले आए थे। उससे जो नैरेटिव सेट हुआ उसे बदलने के लिए आरएसएस ने खुद मोर्चा संभाल लिया था। आरएसएस ने बीजेपी के लिए पूरा जोर लगाया था। कहा जा रहा है कि इसी वजह से महाराष्ट्र में वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ। आपको बताते हैं कि संघ ने महाराष्ट्र में पर्दे के पीछे रहकर कैसे काम किया।

जहां से आरएसएस की उत्पत्ति हुई और इसका मुख्यालय भी जहां स्थित है वहां कैडरों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे एक राजनीतिक और सांस्कृतिक बाजीगर क्यों बने हुए हैं। अपने वैचारिक राजनीतिक पक्ष में हवा के रुख को मोड़ने के लिए रणनीतियों के साथ हिंदुत्व के ताने बाने को सहजता से बुनने में माहिर माना जाता है। मुंबई के औद्योगिक

केंद्रों से लेकर विदर्भ के कृषि क्षेत्रों तक, आरएसएस कार्यकर्ताओं की जमीनी स्तर की लामबंदी ने हिंदू वोटों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संघ के संगठन और बीजेपी के बड़े नेता लगातार बैठके कर रहे थे। संघ के साथ वीएचपी, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय मजदूर संघ के साथ भी बड़े बीजेपी नेताओं की बैठक हो रही थी। हाल ही में विपक्ष की तरफ से स्थापित जातिगत रेखाओं को तोड़कर एक नया चुनावी गणित तैयार किया है। विपक्ष के नरेटिव को तोड़ने के लिए संघ ने 13 अलग अलग ग्रुप बनाए। इनका काम ग्राउंड पर जाना और सोशल मीडिया पर विपक्ष के नैरेटिव को काउंटर करना था। संघ ने महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों पर घर घर जाकर कैंपेन किया। संविधान खतरे में है वाले नैरेटिव की काट घर घर संविधान से दिया गया। आरएसएस ने घर-घर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हमारे सजग रहो मंत्र के साथ, संघ के नेटवर्क ने बूथ स्तर पर चुपचाप काम किया।

आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि हम विशेष रूप से विदर्भ, कोंकण, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में बिखरे हुए समुदायों को सफलतापूर्वक एकजुट कर सकते हैं, जहां जातिगत वफादारी अक्सर मतदान के पैटर्न को निर्धारित करती है। हिंदुत्व के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके और सड़कों पर दिखाई देने वाली मुस्लिम आक्रामकता के बारे में चिंताओं को संबोधित करके, संघ ने मध्यम वर्ग के भीतर बढ़ती नापसंदगी का फायदा उठाया। यह मौन एकजुटता महत्वपूर्ण 4-5 प्रतिशत वोट स्विंग में बदल गई, जिससे भाजपा का आधार उसके पारंपरिक समर्थन आधार और गढ़ों से आगे बढ़ गया। संघ ने मराठा, आदिवासी और दलित समाज नेताओं को प्रचार में लगाया। सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग के लिए इंफ्ल्यूएंशर को अलग से टीम बनाई। संघ की इस मेहनत का असर आज नतीजों के रूप में सामने हैं।

हरियाणा चुनाव के नतीजों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि कैसे ग्रामीण और शहरी इलाकों में आरएसएस की पैठ ने शासन और जमीनी स्तर की चिंताओं, कुछ परस्पर विरोधी जातियों के बीच की खाई को सफलतापूर्वक पाट दिया और भाजपा को अपने राजनीतिक परिणामों को आकार देने में मदद की। बेरोजगारी, जातिगत गतिशीलता या सांस्कृतिक पहचान से लेकर क्षेत्रीय असंतोष को भुनाने की संगठन की क्षमता ने इसे भाजपा के लाभ के लिए मतदाता-भावना को प्रभावित करने की अनुमति दी है। इसका व्यवस्थित और कैडर-संचालित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि मुद्दों को न केवल उठाया जाए बल्कि उनका समाधान भी किया जाए। इसी तरह, महाराष्ट्र में संघ ने राजनीतिक रूप से जटिल राज्य में रणनीतियों को पुनर्व्यवस्थित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। भाजपा की गठबंधन चुनौतियों के साथ-साथ शिवसेना और राकांपा के भीतर विभाजन के बावजूद, संघ का जमीनी कार्य मतदाताओं को एकजुट करने में सहायक रहा है। मराठा वोटों में बिखराव का भी महायुति और बीजेपी को फायदा मिला।

मुंबई जैसे औद्योगिक क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगारी के मुद्दों, आर्थिक स्थिरता और कानून व्यवस्था के आसपास मध्यम वर्ग की चिंताओं पर जोर दिया। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना द्वारा अपनाए गए उद्योग-विरोधी और व्यापार-विरोधी रुख ने वास्तव में शहरी मतदाताओं को निराश किया था। इसके विपरीत, मुंबई पेरिफेरल रोड परियोजना और अन्य विकास जैसी पहल, जबकि लाडली बहना जैसी लक्षित नीतियां महिलाओं और शहरी गरीबों जैसे मुद्दे को टच करना लोगों को भा गया।

महिला मतदाताओं की मुखरता से बदल रही चुनावी नतीजों की तस्वीर

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

महाराष्ट्र विधान सभा के चुनावों ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी नतीजों को बदलने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों में महिलाओं के 6 प्रतिशत अधिक मतदान ने चुनावी परिणामों को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इसी साल की शुरुआत में हुए लोकसभा के चुनाव परिणामों से महाराष्ट्र में कांग्रेस नीत महाअघाड़ी गठबंधन अतिउत्साह में था और लगभग यह मानकर ही चल रहे थे कि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे उनके पक्ष में ही होंगे। अत्यधिक आत्मविश्वास के चलते चुनावी अभियान को सही दिशा व समझ नहीं बैठा पाएं और इसका परिणाम यह रहा कि भाजपा नीत गठबंधन ने विजय के सारे रेकार्ड तोड़ दिए। माने या ना माने पर इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनावी नतीजों को बदलने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका रही।

मध्यप्रदेश से निकली लाड़ली बहना महाराष्ट्र तक आते आते माझी लाड़की बहना योजना ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसी साल लागू करने और चुनाव से पहले ही तीन किश्तें लक्षित महिलाओं के खातों में जाने से पूरा माहौल ही बदल गया। योजना शुरु करने पर विपक्ष ने विरोध किया और यहां तक कि कोर्ट में जनहित याचिकाएं लगाई गई पर कोर्ट द्वारा योजना को सही ठहराने और सीधे खाते में पैसे आने से महिलाओं में सरकार के प्रति विश्वास जगा वहीं महाअघाड़ी गठबंधन महिलाओं से जुड़ी इस योजना को समझने में ही देरी कर दी और भले ही बाद में चुनाव घोषणा पत्र या यों कहे कि चुनावी वादों में अधिक पैसा देने का वादा भी किया पर महिलाओं का विष्वास नहीं जीत पाएं। परिणाम सामने हैं जो मिल रहा है वह बढ़कर मिलेगा इस पर महिलाओं ने अधिक विश्वास जताया। सही मायने में देखा जाए तो महिला शक्ति गेम चेंजर बन कर सामने आई। कहा तो यहां तक जाने लगा है कि महिलाएं जिनके साथ है सत्ता भी उनके हाथ ही लगेगी।

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में चुनावों में महिलाओं की बढ़ती सक्रिय भागीदारी तारीफे काबिल है। गत चुनावों चाहे वे लोकसभा के हों या राज्यों की

विधानसभाओं के देश की महिला वोटरों ने नई सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मजे की बात यह भी है कि चुनाव में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं ने अधिक मुखर होकर मतदान किया है। अब तो यह माना जाने लगा है कि देश के एक दर्जन के करीब राज्यों में महिलाओं के वोट ही नई सरकार के गठन में बड़ी भूमिका निभाने लगे हैं। तस्वीर का सकारात्मक पक्ष यह भी है कि मतदान ही नहीं चुनावों में सक्रियता से हिस्सा लेने और चुनावों में उम्मीद्वारी जताने में भी महिलाएं आगे आई हैं। देश के पहले और दूसरे लोकसभा के आमचुनावों में जहां 22 महिला सांसद चुन कर आई थी वहीं गत 2024 के आमचुनाव में 74 महिला सांसद चुन कर आई। हांलाकि आधी आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नए नए सब्जबाग दिखाने के बावजूद टिकट वितरण के समय महिलाओं की हिस्सेदारी कम ही रह जाती है। अनुभव तो यही बताता है कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा आधी तो दूर की बात एक तिहाई सीटों पर भी महिलाओं को टिकट नहीं दिए जाते है। इस बार महाराष्ट्र चुनावों में 50 महिलाओं को टिकट दिए गए और 21 महिलाएं चुनाव जीत कर विधायक बनी है।

सबसे अच्छी बात यह है कि गॉव हो या शहर महिलाएं अब घर की चार दीवारी में कैद रहने वाली या पुरुष के कहे अनुसार मतदान करने वाली नहीं रही है। पुरुषों के हां में हां मिलाने वाली स्थिति से बहुत बाहर आ चुकी है आज देश की महिलाएं। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में महिलाएं सक्रियता से हिस्सा लेने लगी हैं। चुनावों में उम्मीद्वारी भी जताती है तो चुनाव केंपेन के दौरान अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराती है। दूसरी और मतदान में भी आगे आकर हिस्सा लेने लगी है। देखा जाए तो महिलाओं ने जिस दल पर अधिक भरोसा जताया या यों कहे कि जिस दल को अधिक मत दिए उसी दल की सरकार बनी। मजे की बात यह है कि

अब सभी राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के हर संभव प्रयास में जुटे हैं। यही कारण है कि महिलाओं को लुभाने वाली योजनाएं और कार्यक्रम ना केवल घोषित किये जा रहे हैं अपितु राजनीतिक दलों के आने वाले चुनाव घोषणा पत्रों में महिला मतदाताओं को लुभाने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। क्योंकि एक बात साफ हो चुकी है कि आज की महिला स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है और उसकों दबाव या अन्य तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सकता। कम से कम चुनावों के परिणाम तो इसी और इंगित कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि माझी लड़की बहना योजना में 2.50 लाख आय वाली 18 से 60 साल की महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया। इससे यह साफ हो जाता है कि यह वर्ग कमजोर आर्थिक आय वाली महिलाओं का है। यहां साफ हो जाता है कि महिलाओं का यह वर्ग वो वर्ग है जिसके बारें में यह माना जाता है कि इस वर्ग में महिलाएं पुरुषों के निर्णयों पर अधिक निर्भर होती है पर महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों के चुनावी नतीजों से यह साफ हो गया है कि महिलाएं पुरुषों की हां में हां ना मिलाकर स्वयं निर्णय लेने लगी है और उसीसे ताजा नतीजें रुबरु कराते हैं।

खैर यह अलग बात है, पर यह साफ हो चुका है कि देश के लोकतंत्र के इस महापर्व में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही है। अब महिला मतदाताओं को कमतर नहीं आंका जा सकता। महिला सशक्तिकरण की दिषा में भी इसे शुभ संकेत माना जा सकता है। इसे देश और लोकतंत्र दोनों के लिए ही सकारात्मक प्रयास कहा जा सकता है तो दूसरी और दुनिया के देशों के लिए भी भारत की महिलाएं एक मिसाल बन कर सामने आ रही हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि भविष्य के चुनावों में भी राजनीतिक दलों को सत्ता का स्वाद चखना है तो निगाहें महिला मतदाताओं की और रखनी ही होगी।

जेल से लौटकर असली 'किंग' बने हेमंत

विनोद पाठक

झारखंड में इंडी गठबंधन सत्ता को बरकरार रखने में कायम रहा है। रुझानों में एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार बनती दिख रही है। भाजपा की कोशिश थी कि आदिवासी बाहुल्य राज्य में सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन सात महीने पहले संपन्न लोकसभा चुनाव से स्पष्ट हो गया था कि भाजपा के लिए झारखंड में राह आसान नहीं है। राज्य में इंडी गठबंधन की जीत का श्रेय हेमंत सोरेन को जाता है। वही असली किंग बनकर उभरे हैं। हालांकि, उनके चार मंत्री हार की कगार पर दिख रहे हैं।

राज्य के चुनावी नतीजों को देखने के लिए लोकसभा चुनाव-2024 की ओर जाना होगा। राज्य की 14 लोकसभा सीटों में भाजपा को आठ सीटें मिली थीं, जो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से तीन कम थीं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने तीन सीटें जीतीं और दो सीटों का उसे लाभ हुआ था। सहयोगी कांग्रेस ने भी दो सीटें जीती थीं और उसे एक का इजाफा हुआ था।

हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में पूरी ताकत लगाई और बहुमत पाने का दावा किया, लेकिन भाजपा ने कुछ गलतियां भी झारखंड को लेकर कीं। विशेष कर हेमंत सोरेन को जेल भेजना पार्टी को भारी पड़ा। जेल जाने की सहानुभूति हेमंत सोरेन के पक्ष में गई है। लोकसभा चुनाव से आदिवासी वोट भाजपा से दूर होता दिख रहा था। राज्य की आदिवासियों के लिए रिजर्व पांचों सीटों पर भाजपा हार गई थी।

चुनाव में भाजपा ने ध्रुवीकरण का कार्ड भी खूब खेला। आदिवासी बनाम मुस्लिम वोटों को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया गया। हर सभा में बताया गया कि राज्य में आदिवासी कम हो रहे हैं और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा के हर स्टार प्रचारक ने झारखंड की डेमोग्राफी बदलने के मुद्दे को जोर-जोर से उठाया। खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों और धर्मांतरण पर फोकस किया गया। कैसे आदिवासी लड़कियों से शादी कर घुसपैठिए जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं? हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया।

जमानत पर जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन ने आदिवासी अस्मिता के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। उन्होंने और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मिलकर राज्यभर में 200 से ज्यादा चुनावी सभाओं को संबोधित किया। कल्पना सोरेन ने अपनी सभाओं में महिलाओं पर फोकस रखा। हेमंत सोरेन सरकार की मंईयां सम्मान योजना ने तुरुप के पत्ते का काम किया। चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में हजार रुपए आना शुरू हो गए थे। सोरेन ने आगामी दिसंबर से महिलाओं के खातों में ढाई हजार रुपए डालने की घोषणा की है। महिलाओं में चुनाव को लेकर जबर्दस्त उत्साह भी शायद इसलिए दिखा। महिला वोटरों ने 81 में से 68 सीटों पर पुरुषों की तुलना में अधिक वोट डाले।

हेमंत सोरेने ने अपने गठबंधन के साथी कांग्रेस को चुनाव में थोड़ा पीछे ही रखा। कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को छोड़कर कोई बड़ा नेता झारखंड में प्रचार के लिए नहीं आया। यहां तक की प्रियंका गांधी वाड्रा झारखंड में एक भी सभा करने नहीं आईं। झारखंड में जीत का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो हेमंत सोरेन को जाता है। उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक चुनाव का मैनेजमेंट किया। झारखंड में जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा की हुई है। यहां इंडी गठबंधन का प्रभाव नहीं दिखा। कांग्रेस को भले पिछली बार के बराबर ही सीटें मिल रही हैं, लेकिन असली किंग हेमंत सोरेन हैं।

ठंड के मौसम में डैंड्रफ से हैं परेशान तो इन आसान उपाय को अपनाकर पाएं छुटकारा

ठंड के मौसम में डैंड्रफ होने की समस्या आम हो जाती है। ये सिर्फ हमारे बालों को नुकसान ही नहीं पहुंचाती बल्कि शर्मिंदा भी करती है। इसे दूर करने के लिए कैमिकल युक्त शैम्पू, कंडीशनर का ज्यादा इस्तेमाल करने के बजाय कुछ अन्य उपाय किए जाएं, तो बालों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है आइए जानते हैं कुछ टिप्स.

नारियल का तेल

नारियल का तेल रूसी के लिए एक बेहतरीन उपाय है। नहाने से पहले 4-5 चम्मच नारियल के तेल से मालिश करें और 1-2 घंटे बाद बालों को धो लें। रातभर लगाकर भी छोड़ सकते हैं। इससे डैंड्रफ में राहत मिलती है। ऐसा शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते है जिसमें नारियल तेल हो।

शैम्पू करने से पहले डैड्रफ को साफ करने के लिए नमक बहुत कारगर है। नमक को स्कैल्प पर डालकर हल्कें हाथों से रगड़ें इससे मृत त्वचा निकलने लगेगी। कुछ देर रगड़ने के बाद शैम्पू कर लें। आप पाएंगे कि डैंड्रफ पहले से काफी कम हो रहे है। जब भी शैम्पू करें इस प्रक्रिया को अपनाएं कुछ ही समय में डैंड्रफ से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा।

नींबू का रस

दो चम्मच नींबू के रस को अपने बालों के स्कैल्प पर रगड़कर इससे अच्छी तरह से मालिश करें। फिर एक कप पानी में एक नींबू का रस मिलाएं अब इस पानी से अपने बालों को साफ करें। ऐसा आप हफ्ते में 3 बार करें।

नारियल और नींबू का रस

नारियल के तेल में एक चम्मच नींबू का रस डालकर इन्हें हल्का गर्म कर लें। अब इस तेल से अपने बालों की मसाज करें। फिर शैम्पू से अपने बालों को धो लें। ये प्रक्रिया आप हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर करें।

कामकाजी महिलाओं को हमेशा रखना चाहिए इन बातों का ध्यान

शादी के बाद एक लड़की को अपने पति से ही नहीं बल्कि अपनी सास-ससुर से भी अच्छा तालमेल बनाने की जरूरत है। लेकिन तब क्या हो जब आप घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों के चलते बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रही हों।

वो जमाना गया जब महिलाएं घर की चार दीवारी में रहकर ही अपना पूरा जीवन काट देती थीं। आज की महिलाएं न केवल अपने अधिकारों को लेकर स्वतंत्र हैं बल्कि पुरुषों की तरह घर से बाहर निकल अपनी एक अलग पहचान बनाने में भी कामयाब हो रही हैं। हां, वो बात अलग है कि लाख-पढ़ी लिखी होने के बाद भी लड़कियों को ससुराल जैसी पारंपरिक भूमिकाओं से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें न केवल अपने पति के दिल में जगह बनानी होती है बल्कि अपने सास-ससुर संग एक अच्छे रिश्ते की शुरूआत करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी में से एक है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत कामकाजी महिलाओं के साथ है, जिन्हें हर पल इस बात की चिंता सताती रहती है कि घर और ऑफिस के बीच क्या वह अपनी संतुलन भूमिकाएं निभा भी पाएंगी या नहीं?

खैर, हम इस तर्क-वितर्क से किसी नतीजे पर पहुंचें उससे पहले आपको बता दें कि जहां कुछ महिलाओं ने एक संयुक्त परिवार में रहने के कई दोष बताएं हैं तो वहीं इसके विपरीत कई कामकाजी महिलाओं का ऐसा कहना है कि एक संयुक्त परिवार में रहना आपके लिए एक मजबूत समर्थन बन सकता है बशर्ते आपको काम और घर के बीच बैलेंस बनाना आता हो। ऐसे में अगर आप भी चाहती हैं कि कम समय में ही आप सभी की लाडली बन जाए तो आपको इन बातों का हमेशा ध्यान रखें।

काम के साथ घर को भी प्राथमिकता

हम इस बात को अच्छे से समझते हैं कि एक लड़की के लिए उसका करियर कितना महत्व रखता है लेकिन शादी के बाद आपको यह भी समझना चाहिए कि अब आप अकेले नहीं है आपका अपना एक परिवार है, जिसके हिसाब से भी अब आपको चीजों को मैनेज करना होगा। शादी से पहले जहां घंटों-घंटों आप ऑफिस में काम करती थीं तो वहीं अब आपको अपने परिवार के लिए भी समय निकालना होगा साथ ही साथ घर खर्च के हिसाब से लेकर पार्टनर के माता-पिता की देखरेख करने तक आपको कई बातों को भी ध्यान रखना होगा।

सुनें और समझें

अगर आप वाकई में चाहती हैं कि आप काम के साथ-साथ अपने परिवार की भी लाडली बनी रहीं तो सबसे पहले बातों को सुनने और समझने की आदत डालें। ऐसा करने से न केवल आप अपने सास-ससुर के मन की बातों को जान पाएंगी बल्कि वह भी आपके काम के महत्व को समझेंगे। यही नहीं, अपने परिवार के हर सदस्यों को जानने की कोशिश करें। यही नहीं, साथ ही साथ उन्हें यह भी बताएं कि घर की जिम्मेदारी को निभाने में आपके लिया क्या संभव है और क्या नहीं।

पति से हो खुलकर बातचीत

किसी ने ठीक ही कहा है कि सबसे अच्छी शादी वह होती है जिसमें पति-पत्नी एक-दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हों। अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ प्यार करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। ऐसे में कोशिश करें कि आप और आपके पति के बीच एक स्वस्थ दोस्ती का रिश्ता हो। इसके बाद आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुद फर्क समझ आ जाएगा। वह न केवल आपको समझेंगे बल्कि आपको घर-परिवार की जिम्मेदारी का एहसास होगा।

पहली मुलाकात में जानें एक-दूसरे को

जब भी कपल्स एक-दूसरे से मिलने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले जेहन में ये बात जरूर आती है कि आखिर पहली मुलाकात में हम बात क्या करेंगे? यही सवाल हमें परेशान करता रहता है और वैसे भी पहली-पहली मुलाकात तो बहुत खास होती है, जो हमेशा याद रहती है।

लेकिन इस मुलाकात में हम एक-दूसरे से बात ही न कर पाएं या यूं कहें कि उस समय क्या बात करें? ये समझ ही न आए तो क्या करें? क्योंकि हमने आमतौर पर देखा है कि हमारे मन में बातें तो ढेरों रहती हैं, लेकिन पहली मुलाकात पर वे बातें जुबान पर आ ही नहीं पातीं और हम शांत बैठे रह जाते हैं। और यहां-वहां देखकर बस यही सोचते रह जाते हैं कि बातें करें तो क्या? आखिर क्या बातें फर्स्ट मीटिंग में करें? कैसे बातों से एक-दूसरे को समझने में आसानी हो सकती है? ऐसी कौन सी बातें हैं, जो आपके पार्टनर को बोर नहीं होने देंगी? आइए जानते हैं।

जब भी किसी के साथ पहली मुलाकात के लिए जाएं तो बातों की शुरुआत आप उनके प्रोफेशन से कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसमें इंट्रेस्ट जरूर आता है। चाहे प्रोफेशन के बारे में गॉसिप अच्छी हो या बुरी, इस बारे में बात करना लोग काफी पसंद करते हैं। पार्टनर के फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में आप पूछ सकते हैं या अभी रिसेंट उन्होंने कौन सी मूवी देखी है? इस बारे में भी आप बात कर सकते हैं। तारीफ किसको पसंद नहीं आती? जनाब तो कॉम्प्लीमेंट करना बिलकुल भी न भूलें। उन्हें नोटिस करें और उनकी तारीफ कीजिए। आप उनके ड्रेसिंग सेंस की तारीफ कर सकते हैं। दोस्तों के बारे में बात करें, क्योंकि लड़का हो या लड़की-सभी को अपने दोस्तों के बारे में बात करना पसंद आता है। तो आप पूछ सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? किस फ्रेंड्स से अपनी बातें शेयर करते हैं? इस तरह की बातें आपकी मुलाकात को और इंट्रेस्टिंग बनाएंगी। वीकेंड के बारे में पूछें कि उनके इस वीकेंड क्या प्लान हैं? यदि कोई प्लान नहीं हैं, तो आप प्लान कर सकते हैं जिससे कि एक-दूसरे को अच्छे से समझने के लिए और समय मिल सके। अगर बातें बोरिंग हो रही हैं तो आप हंसी-मजाक कर सकते हैं कि उनके साथ ऐसा वाकया कब हुआ, जब उनकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। ऐसी कोई फनी बात, जो आपके साथ हुई हो तो वह बात भी आप उनसे शेयर कर सकते हैं।

कुर्ते से लगें स्मार्ट

कुर्ते आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं, जितने पहले थे। बस, इसकी स्टाइल में थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। आजकल पाकिस्तानी सूट ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। लड़कियां जोधपुरी शैली के सलवार कुर्ते भी बनवाना पसंद करती हैं। ये कुर्ते ढीले-ढाले और कई रंगों में उपलब्ध होते हैं। आम तौर पर लोगों की राय है कि आज के आधुनिक युग में लड़कियां जींस आदि पहनना ही पसंद करतीं हैं और सलवार कुर्ते तथा अन्य पारंपरिक कपड़ों का चलन कम हो रहा है, लेकिन फैशन डिजाइनरों की राय इससे अलग है। उनका कहना है कि आज भी लड़कियां सलवार कमीज बनवाना पसंद करतीं हैं और अब तो इसमें रेट्रो फैशन की झलक भी देखने को मिल रही है। आजकल तो लड़कियां जींस के साथ भी लांग और शार्ट कुर्ते पसंद करतीं हैं। सलवार के साथ शार्ट कुर्ते या अनारकली स्टाइल के कुर्ते ज्यादा देखे जा रहे हैं। संगीता का कहना है कि कुर्ते को जींस, लेगिंस और जेगिंस, मतलब डेनिम स्टाइल की जींस की तरह दिखने वाली सलवार के साथ पहनने का फैशन काफी प्रचलन में है। केवल सलवार कमीज ही नहीं, दुल्हन के लहंगों में भी आधुनिकता और पारंपरिकता का मिश्रण देखने को मिल रहा है। सलवार कमीज का जादू कुछ और ही होता है। इस आउटफिट में थोड़ी सी तब्दीली करते ही इसे इंडो वेस्टर्न लुक दिया जा सकता है। आइए जानते हैं सलवार-कुर्ते से जुड़े कुछ टिप्स-

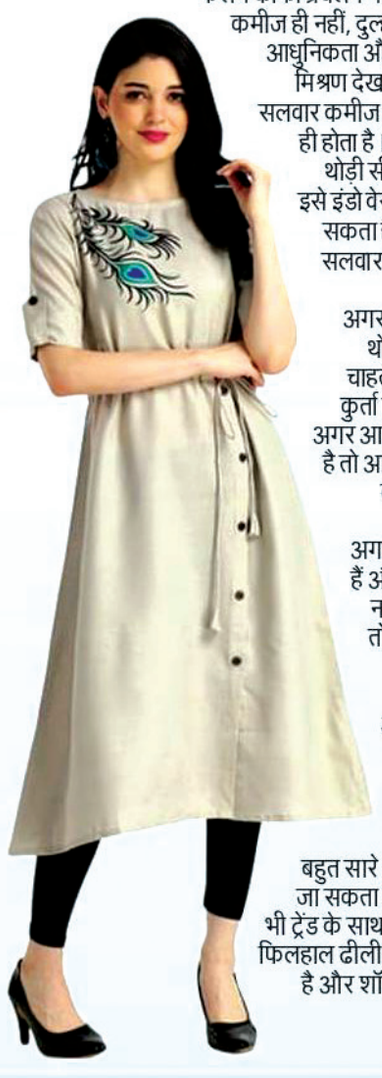

अगर आप अपनी हाइट थोड़ी ज्यादा दिखाना चाहती हैं, तो थोड़ा लंबा कुर्ता सिलवाएं। मसलन अगर आपकी हाइट 5 '3'' है तो आपको 47-48 इंच का कुर्ता सिलवाना चाहिए।

अगर आपके हाथ मोटे हैं और आप स्लीवलेस नहीं पहन सकती हैं, तो 5 इंच की स्लीव्स बनवा लें। इससे आपके हाथ का अतिरिक्त मांस भी छिप जाएगा और आपके हाथ दुबले दिखेंगे। सलवार को बहुत सारे स्टाइल्स में पहना जा सकता है। इनका स्टाइल भी ट्रेंड के साथ बदलता रहता है। फिलहाल ढीली सलवार फैशन में है और शॉर्ट कुर्ते ने एक बार फिर एंट्री की है।

क्या आप जानते हैं लेगिंग्स पहनने का सही तरीका

जब भी कम्फर्ट की बात आती है तो सबसे पहले हम लेगिंग्स के बारे में सोचते हैं, क्योंकि लेगिंग्स काफी आरामदायक होती है। लेकिन इसे पहनने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हम हंसी के पात्र बन जाते हैं।

क्या आप जानती हैं लेगिंग्स पहनने का सही तरीका? अगर हां तो यह बहुत बढ़िया बात है और यदि आपका जवाब ना है तो इस लेख को पढ़कर आप इस बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं।

हमने अक्सर ऐसी कुछ महिलाओं को देखा है, जो लेगिंग्स के साथ क्रॉप टॉप ट्राई कर लेती हैं। लेकिन यदि आप भी ऐसी गलती करती हैं तो इसे छोड़ दें, क्योंकि लेगिंग्स के साथ कभी भी क्रॉप टॉप नहीं पहना जाता। यह दिखने में बहुत भद्दा लगता है।

ये तो बात हुई क्रॉप टॉप कि लेकिन अगर आप छोटे टॉप पर लेगिंग्स पहनने का विचार कर रही हैं तो इसे बिलकुल भी ट्राई न करें, भले ही आप कितनी भी स्लीम ट्रीम क्यों न हों, पर छोटे टॉप के साथ लेगिंग्स की यह स्टाइल आप पर बिलकुल अच्छा नहीं लगेगी। आपको ऐसी अंडरवियर पहनना चाहिए जिसमें हेमलाइन लेगिंग्स के ऊपर नजर न आए। ऐसे लेगिंग्स पहनने में बहुत अजीब सा लगता और आप इसमें कम्फर्टेबल भी नहीं रह सकती हैं।

प्रिंटेड लेगिंग्स को न करें ट्राई

आप प्रिंटेड लेगिंग्स ट्राई न ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये पहनने में बिलकुल भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए अगर आप लेगिंग्स लेने जा रही हैं, तो प्रिंटेड लेगिंग्स न ही लें तो बेहतर है।

पाएं हाई हील्स की तकलीफ से छुटकारा

अधिकतर लड़कियां हिल्स पहनना तो चाहती है, लेकिन उन्हें लगता है कि इसे पहनना काफी तकलीफभरा हो सकता है, लेकिन एक अच्छी और स्टाइलिश ड्रेस के साथ हिल्स काफी अच्छी लगती है पर पैरों की तकलीफ के कारण इसे नहीं चुनते हैं। लेकिन हम यहां आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे है जिन्हें अपनाकर आप हाई हिल्स में कंफर्टेबल हो सकती है हम ये नहीं कहते कि हिल्स में आप बहुत आरामदायक महसूस करेंगी लेकिन कुछ टिप्स को अपनाकर आप हाई हिल्स पहनने से होने वाली दिक्कतों से बच सकती हैं.तो आइए, जानते हैं कि हाई हील्स पहनने के दौरान होने वाली परेशानी को आप कैसे कम कर सकती हैं

सैंडिल के सही साइज का चुनाव करें

हील्स वाली सैंडिल में आपके पैर आगे की ओर पुश होते हैं, ऐसे में अपने लिए सही साइज की सैंडिल का चुनाव करें।

अपना फुट टाइप पहचानें

सभी के फुट अलग-अलग होते हैं, किसी के पैर के पंजे चौड़े तो किसी के पतले होते हैं। अपने पंजे के अनुसार सैंडिल के आगे की डिजाइन चुनें, जिससे कि आपके पैर आगे से दबे नहीं।

मोटी हील को प्राथमिकता दें

मोटी हील आपके पैरों को ज्यादा कवरेज और सपोर्ट देती हैं। इसे पहनने से आपकी एड़ियों पर कम दबाव पड़ेगा, जिससे पैरों में दर्द भी कम होगा।

ब्रेक लें

पार्टी व किसी खास अवसर पर ही हाई हील्स पहनें। यदि इसके अलावा भी पहनें तो कभी-कभी फ्लेट चप्पल पहनें और अपने पैरों को थोड़ा ब्रेक दें।

हील की पोजीशन का ख्याल रखें

आपके जूते ऐसे होने चाहिए जिसमें बॉडी का भार पंजों और हील दोनों पर रहे। वरना पंजो या फिर हील पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। ऐसा होने पर पैरों में दर्द शुरू हो सकता है। इसलिए हील की पोजीशन का ख्याल जरूर रखें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सस्पेंस के बीच एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से दिया इस्तीफा

मुंबई। शीर्ष पद के लिए महायुति के अगले दावेदार के चयन पर सस्पेंस के बीच शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शिंदे ने मुंबई के राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। उनके प्रतिनिधि अजित पवार और देवेन्द्र फडणवीस भी मौजूद थे। हालांकि, नई सरकार बनने तक शिंदे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे। भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने चुनावों में भारी जीत हासिल की और 288 सदस्यीय विधानसभा में 235 सीटें हासिल कीं। हालाँकि, गठबंधन अब तक इस बात पर आम सहमति बनाने में विफल रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। शिवसेना ने कहा है कि शिंदे को राज्य का नेतृत्व जारी रखना चाहिए, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि माझी लड़की बहिन योजना, जो चुनावों में गेम-चेंजर साबित हुई, उनके दिमाग की उपज थी।

केंद्र सरकार ने 5 साल बढ़ाया उग्रवादी संगठन उल्फा पर बैन

नईदिल्ली। केंद्र ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) पर पांच साल के लिए नया प्रतिबंध जारी किया, जिसमें कहा गया कि यह समूह 2019-24 के दौरान विस्फोटक लगाने के 16 मामलों में शामिल रहा है और पूरे असम में स्वतंत्रता दिवस, 2024 से पहले इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) का इस्तेमाल किया है। केंद्र ने अब तक केंद्र, राज्य और असम, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड सहित पूर्वोत्तर में विद्रोही समूहों के बीच 12 त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के वार्ता विरोधी गुट, जिसे उल्फा के नाम से भी जाना जाता है (स्वतंत्र) शांति प्रक्रिया के लिए मायावी बना हुआ है। यह संगठन पूर्वोत्तर का एकमात्र प्रमुख संगठन है जो सरकार के साथ शांति वार्ता से बाहर है। उल्फा (स्वतंत्र) का नेतृत्व परेश बरुआ कर रहे हैं।

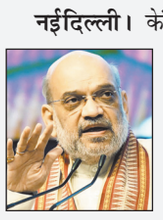

हार से बौखलाए संजय राउत ने चंद्रचूड़ को ठहराया जिम्मेदार

मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर संशय के बीच शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने दावा किया कि मेरे हिसाब से देवेन्द्र फडणवीस अगले सीएम होंगे। उन्होंने कहा कि सीएम का फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। एकनाथ शिंदे और अजित पवार अपनी पार्टियों के लिए फैसले खुद नहीं ले सकते। ये दोनों पार्टियां अमित शाह और पीएम मोदी की गुलाम हैं और बीजेपी की उपकंपनियां हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी के पास बहुमत है। वो बहुमत के लिए एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी को तोड़ सकती है। इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि इस चुनाव में ईवीएम एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए इस बार हम कहते हैं कि ये नतीजा तो आने दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र में ये चुनाव एक बार फिर पेपर बैलेट से करा लीजिए और फिर दिखा दीजिए कि नतीजे वही आते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब बातें जो हैं महाराष्ट्र में हुआ है, डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं।

लोग यह न मानें कि न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाएगी: चंद्रचूड़

नई दिल्ली। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक साक्षात्कार में न्यायपालिका की भूमिका को लेकर स्पष्ट जवाब दिए। दरअसल, चंद्रचूड़ की यह टिप्पणी राहुल गांधी के उस बयान को लेकर आई, जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा था कि विपक्ष ने न्यायपालिका का काम करने की जिम्मेदारी भी खुद पर ही ले ली है। इस पर पूर्व सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका यहां कानूनों का परीक्षण करने के लिए है और लोगों को यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह (न्यायपालिका) संसद और राज्यों की विधानसभा में विपक्ष की भूमिका भी निभाएगी। एक इंटरव्यू में चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक विपक्ष के लिए अलग जगह है। उन्होंने कहा, मैं इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता के साथ शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि हम यहां इस मुद्दे पर बात करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कई बार यह गलतफहमी होती है कि न्यायपालिका की भूमिका विधायिका में विपक्ष की होती है, जबकि ऐसा नहीं है। हम यहां कानूनों के परीक्षण के लिए हैं।

मिल्कीपुर चुनाव का रास्ता साफ होने के बाद बढ़ी चुनावी हलचल

लखनऊ। मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ होने के बाद एक बार फिर से राजनीतिक हलचल बढ़ने की उम्मीद है। चुनाव टलने के बाद राजनीतिक दलों की दौड़ भाग कम हो गई थी। 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश की नौ विधानसभा सीटों के उपचुनाव के आए नतीजों से लबरेज भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में कमल खिलाकर फैजाबाद सीट हारने का धब्बा मिटाना चाहती है। आम चुनाव में भाजपा से यह सीट छीनकर अपनी झोली में डालने वाली समाजवादी पार्टी भी इसे कतई गंवाना नहीं चाहती। इसके लिए वह पूरा दमखम लगाने के लिए तैयार है। अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा व एक अन्य की याचिका वापस होने के बाद मिल्कीपुर में चुनाव के रास्ते खुल गए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर 15 अक्तूबर के पहले भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के प्रदेश एवं राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जगह-जगह चौपाल लगाकर प्रचार-प्रसार शुरू किया था।

हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज : राष्ट्रपति मुर्मू

नई दिल्ली। मंगलवार को संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। यह संयुक्त सत्र संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित हुआ। मंगलवार को देश में संविधान लागू होने के 75 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया। साथ ही राष्ट्रपति ने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति ने संस्कृत भाषा में संविधान की प्रति का विमोचन भी किया।

संविधान दिवस पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार बन रहे हैं। 75 साल पहले संसद के इसी कक्ष में देश के संविधान के निर्माण का बहुत बड़ा काम संपन्न किया और उसी दिन इस संविधान को अपनाया गया। संविधान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से संविधान सभा के सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। बाबा आंबेडकर ने संविधान सभा का नेतृत्व किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। इसी भावना के साथ हम इस विशेष अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। हमें उन अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद रखना चाहिए, जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया और देश के संवैधानिक मूल्यों को मजबूती दी। जिनमें प्रमुख भूमिका बीएन राव की थी, जो संविधान सभा के सलाहकार थे। आगामी 26 जनवरी को हम अपने गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ बनाएंगे। ऐसे समारोह हमारी राष्ट्रीय एकता को दर्शाते हैं। हमारी संविधान सभा में देश की विभिन्नता में एकता प्रदर्शित हुई थी। आज जिन पुस्तकों का विमोचन किया गया, उनमें लोगों को हमारे संविधान निर्माण के गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चलेगा। हमारा संविधान कई वर्षों की मेहनत से बना, लेकिन ये हमारी आजादी की लड़ाई का परिणाम था। संविधान में भारत के आदर्शों,

न्याय, स्वतंत्रता और समानता को भी परिलक्षित किया गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान की भावना के अनुसार, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का दायित्व है कि वे लोगों की भलाई के लिए मिलजुलकर काम करें। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए जीएसटी लागू किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से एक नए युग की शुरुआत की गई। सरकार ने सभी वर्गों खासकर पिछड़े वर्ग की भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं। गरीब लोगों को पक्का घर, बिजली पानी सड़क की सुविधा मिल रही है। चिकित्सा सेवाएं मिल रही हैं और देश में बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है। इन प्रयासों के लिए मैं सरकार की सराहना करती हूं।

राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका, विचाराधीन कैदियों के कल्याण के लिए भी प्रयासरत है। कम संसाधन युक्त लोगों को न्याय मुहैया कराने की सुविधा बढ़ रही है। इससे हमारे संवैधानिक अधिकारों को शक्ति मिलती है। समाज में समरसता का निर्माण करना, महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना और पर्यावरण आदि क्षेत्रों में काम हो रहा है। हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। हमने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय के अनेक लक्ष्यों को हासिल किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत बनाने का संदेश दिया है। आज देश आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ ही विश्वबंधु के विचारों को बढ़ावा दे रहा है।

राष्ट्रपति ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को याद करते हुए कहा कि संविधान सभा के दूरदर्शी सदस्यों ने एक प्रेरणादायक संविधान दिया, जो अन्य देशों के लिए भी आदर्श है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने आज ही के दिन कहा था कि संविधान को जीवंत बनाए रखना उन लोगों पर निर्भर करता है, जो उसका संचालन करते हैं। जो संविधान में नहीं लिखा जाता उनका संचालन परंपराएं करती हैं। अब तीन चौथाई संविधान यात्रा के बाद देश ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। आने वाली पीढ़ियों को इन सफलताओं से अवगत कराया जाना चाहिए।

मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करती हूं कि वे संवैधानिक मूल्यों को अपने आचरण में डालें। संविधान दिवस की हार्दिक बधाई, जय हिंद, जय भारत।

संविधान सभा की गरिमापूर्ण, रचनात्मक बहस की परंपराओं का पालन करें: बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को संविधान दिवस के अवसर पर सभी संसद सदस्यों से अपील की कि जिस तरह से संविधान सभा में गरिमापूर्ण और रचनात्मक तरीके से बहस हुई, उस परंपरा का पालन किया जाना चाहिए। देश का संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से रचनात्मक बहस करने की अपील की।

ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान सभा ने करीब तीन वर्षों तक संविधान बनाने और देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधता को साथ लाने के लिए कड़ी मेहनत की। हमारे सदनों को भी संविधान सभा की परंपरा का पालन करना चाहिए और रचनात्मक और गरिमापूर्ण बहस करनी चाहिए। ओम बिरला ने कहा, इसी दिन, इस पवित्र सदन में, हमारे संविधान को अपनाया गया था, जो हमारे पूर्वजों के समर्पण, बलिदान और दूरदर्शिता का प्रमाण है।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद ने पिछले साढ़े सात दशकों में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, हमारा संविधान सामाजिक और आर्थिक बदलाव का उत्प्रेरक रहा है, जिसने आम नागरिकों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार किए हैं और लोकतंत्र में उनकी आस्था को गहरा किया है। इस अमृत काल में सामूहिक प्रयास भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर कर रहे हैं।

बिरला ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के बीच संतुलन बनाने में संविधान की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा, 75 वर्षों से लोकतंत्र के इन तीन स्तंभों ने सामंजस्य के साथ काम किया है और भारत के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने संसद सदस्यों से विधायी कार्यवाही में समावेशिता और संवाद को बढ़ावा देने की अपील की। बिरला ने कहा, संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता ने वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को बढ़ाया है, जो वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत का उदाहरण है- दुनिया एक परिवार है।

संविधान दिवस पर खरगे बोले- विचारों की रक्षा के लिए सभी साथ आएं

नई दिल्ली। मंगलवार को संविधान दिवस था और देश संविधान की 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस बीच, कांग्रेस ने नागरिकों से संविधान के मूल्यों की रक्षा करने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि भारत के निहित दर्शन की रक्षा के संघर्ष को इसे अपनाए जाने के 75वें वर्ष में फिर से सशक्त और पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि भारत के लोगों को संविधान में व्यक्त किए गए प्रत्येक विचार की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, संविधान को अपनाए जाने का 75वां वर्ष आज से शुरू हो गया है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों द्वारा बड़ी मेहनत और सावधानी से तैयार किया गया भारत का संविधान हमारे देश की जीवनरेखा है। यह हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की गारंटी देता है। यह भारत को एक संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। उन्होंने आगे कहा कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व केवल आदर्श या विचार नहीं हैं, वे 140 करोड़ भारतीयों के लिए जीवन का तरीका हैं। आज हम संविधान सभा और उसके सदस्यों के जबरदस्त योगदान को याद करते हैं।

हमारा संविधान ही करोड़ों भारतीयों का सुरक्षा कवच: प्रियंका गांधी

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर कहा, मंगलवार को हमारे संविधान के लागू होने का 75वां साल शुरू हो गया है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों ने मिलकर एक ऐसे संविधान का निर्माण किया, जिसने करोड़ों भारतीयों के लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय सुनिश्चित किया। हमारा संविधान ही करोड़ों भारतीयों का सुरक्षा कवच है जो उन्हें हर तरह के अधिकार देता है। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं। महान पूर्वजों, शहीदों, क्रांतिकारियों और संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य को नमन। उनकी अथक मेहनत और कुर्बानियों से मिला यह लोकतंत्र और संविधान हमारा गौरव है। आइए, संकल्प लें कि हम हर हाल में इसकी रक्षा करेंगे।

सभी को स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिलना चाहिए: राहुल गांधी

वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे संविधान की मूल भावना यह है कि न्याय और अधिकार सभी के लिए एक समान होने चाहिए। सभी को स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिलना चाहिए। संविधान समाज के सबसे ग़रीब और कमज़ोर वर्गों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली औजार है। यह जितना मजबूत होगा, हमारा देश उतना ही ताकतवर होगा। आज के दिन, संविधान के सोच की हिफ़ाज़त करने वाले सेनानियों, शहीदों और संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य को नमन करते हुए मैं इसकी रक्षा करने के अपने संकल्प को दोहराता हूं।

खेल
प्रमुख समाचार

05 बार की चैम्पियन टीम मुंबई इंडियंस की सूची

नईदिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 मेगा नीलामी खत्म हो गई है। मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी ने प्रसन्नता जताई कि आईपीएल 2025 में जसप्रीत बुमराह के जोड़ीदार के रूप में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को लेने की योजना कामयाब रही। आईपीएल मेगा नीलामी में मुंबई इंडियंस ने 18 खिलाड़ी पर दांव लगाया। इसमें बोल्ट और बुमराह की जोड़ी इस बार दिखेगी। एमआई ने दीपक चाहर, विल जैक और मिशेल सेंटनर को शामिल किया। टीम में 15 भारतीय और 8 विदेशी खिलाड़ी हैं।

मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 टीम- जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट (12.50 करोड़ रुपये), नमन धीर (5.25 करोड़ रुपये), रॉबिन मिंज (65 लाख रुपये), कर्ण शर्मा (50 लाख रु.), रयान रिकेल्टन (1 करोड़ रु.), दीपक चाहर (9.25 करोड़ रु.), अल्लाह ग़ज़नफ़र (रु.) 4.80 करोड़), विल जैक्स (5.25 करोड़ रुपये), अश्वनी कुमार (30 लाख रुपये), मिशेल सेंटनर (2 करोड़ रुपये), रीस टॉपले (75 लाख रुपये), कृष्णन श्रीजीत (30 लाख रुपये), राज अंगद बावा (30 लाख रुपये), सत्यनारायण राजू (30 लाख रुपये), बेवॉन जैकब्स (30 लाख रुपये), अर्जुन तेंदुलकर (30 लाख रुपये), लिज़ाद विलियम्स (75 लाख रुपये), विग्नेश पुथुर (30 लाख रुपये)।

आकाश अंबानी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुख्य कोच एंडी फ्लावर के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,'ट्रेंट बोल्ट और बुमराह की वापसी हो गई है और हम यह जोड़ी चाहते थे। नीलामी में आप किसी एक खिलाड़ी को तरजीह नहीं दे सकते। हमें खुशी है कि बोल्ट की वापसी हुई है।' अंबानी ने कहा कि अफगानिस्तान के स्पिनर अल्लाह गजांफर को लेने के लिये उन्हें काफी सोच विचार करना पड़ा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

उठापठक के बीच गिरावट में बंद हुआ बाजार!

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिलेजुले रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से जारी तेजी पर मंगलवार को ब्रेक लग गयी। अदाणी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली का असर शेयर बाजार पर देखने को मिला। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज पिछले बंद भाव के मुकाबले 300 से ज्यादा अंक चढ़कर 80,415.47 अंक पर खुला। हालांकि, बाद में यह उतार-चढ़ाव के बाद 100 से ज्यादा अंक गिर गया। अंत में सेंसेक्स 105.79 अंक या 0.13% गिरकर 80,004.06 पर बंद हुआ। इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स लगभग 1000 अंक चढ़कर बंद हुआ था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी मंगलवार (26 नवंबर) को तेजी के साथ 24,343.30 अंक पर खुला। मगर एक घंटे में बाद लाल निशान में फिसल गया। कारोबार के अंत में निफ्टी 27.40 अंक या 0.11% टूटकर बंद हुआ।

एसबीआई में एकमुश्त जमा करें, हर महीने होगी इनकम

नईदिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) कस्टमर्स के लिए कई तरह की डिपॉजिट स्कीम ऑफर करता है। आमतौर पर निवेशकों में फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट ज्यादा पॉपुलर हैं। इसके अलावा एसबीआई की एक स्कीम ऐसी भी है, जिसमें एकमुश्त डिपॉजिट करने के बाद हर महीने ब्याज के साथ इनकम होती है। यहां बात कर रहे हैं, एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम की। इस स्कीम में जमाकर्ता को हर महीने मूलधन के साथ ब्याज दिया जाता है। ब्याज अकाउंट में बची रकम पर हर तिमाही कम्पाउंडिंग पर कैलकुलेट होता है। एसबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम पर वही ब्याज मिलता है, जो रेगुलर और सीनियर सिटीजन के लिए बैंक के टर्म डिपॉजिट यानी एफडी पर मिलता है।

भारत में आईफोन प्रोडक्शन 10 अरब डॉलर के पार

नई दिल्ली। कोई सोच सकता था कि भारत में ऐपल का आईफोन 10 अरब डॉलर का बनेगा, वह भी सिर्फ सात महीनों में। लेकिन आज की तारीख में यह हकीकत है। यह कमाल हुआ है केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के कारण। यही नहीं, अब भारत से काफी मात्रा में आईफोन का एक्सपोर्ट भी होने लगा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 के शुरुआती 7 महीनों के दौरान ही देश में 10 अरब डॉलर के आईफोन का प्रोडक्शन हुआ है। उन्होंने बताया कि इस साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच किए गए 10 अरब डॉलर के उत्पादन में से करीब 7 अरब डॉलर के आईफोन का निर्यात किया गया है। उल्लेखनीय है कि साल 2023-24 के दौरान भारत में कुल 14 अरब डॉलर के आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। इसमें से 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन का निर्यात किया गया था।

फिच ने निगेटिव वॉच में रखे अडानी ग्रुप के कुछ बॉन्ड

नई दिल्ली। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने अडानी ग्रुप के कुछ बॉन्ड्स को नेगेटिव वॉच में डाला है। अमेरिका के अभियोजकों ने अडानी ग्रुप के कुछ अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। इसके बाद फिच ने यह कदम उठाया है। इससे मंगलवार को ग्रुप के शेयरों में 8 प्रतिशत तक की गिरावट आई। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में सबसे अधिक गिरावट देखी गई। यह कारोबार के दौरान 8 प्रतिशत गिरकर 52 सप्ताह के निचले स्तर 893 रुपये पर आ गया। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी टोटल गैस में भी क्रमश: लगभग 5 प्रतिशत और 3 प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। इस बीच, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर और अडानी विल्मर के शेयरों में 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत के बीच की गिरावट आई।

निवेशकों को वित्तीय साधनों के जोखिम के बारे में जानकारी जरूरी

पिनाकी चक्रवर्ती

हालांकि इस वर्ष की पहली छमाही में महंगाई में कमी के संकेत दिखे थे, लेकिन लगता है कि अब इसने गियर बदल लिया है और इसमें वृद्धि होने लगी है। अक्तूबर के महीने में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में वृद्धि खाद्य मुद्रास्फीति के कारण हुई। शेयर बाजार लंबे समय से उच्च स्तर पर चल रहा था। बाजार में बेहद जरूरी सुधार, जो कि अब हो रहा है, की भविष्यवाणी कई विश्लेषकों ने की थी। हालांकि ऐसे में स्थिर मुद्रास्फीति सुधार की प्रक्रिया को तेज करेगी और बाजार में तेजी से सुधार होगा। इस सुधार में वैश्विक कारक भी शामिल हैं। साथ ही कॉरपोरेट बैलेंस शीट पर कमाई का दबाव इस तथ्य को भी दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मांग सामान्य अपेक्षा से भी कम है, जबकि अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में सालाना छह प्रतिशत से

कम दर से नहीं बढ़ रही है। मुद्रास्फीति प्रबंधन के लिए खाद्य और गैर-खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के तरीके के बारे में चर्चा चल रही है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने प्रस्ताव दिया है कि जब रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा ब्याज दर तय की जाती है, तो खाद्य मुद्रास्फीति को उससे बाहर रखा जाना चाहिए। तर्क यह है कि खाद्य मुद्रास्फीति मांग-आपूर्ति प्रबंधन पर निर्भर है। इस प्रकार, ब्याज दर में बदलाव का खाद्य मुद्रास्फीति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

समिति पर विकास को समर्थन देने के लिए ब्याज दर कम करने का भी दबाव है। एमपीसी के समक्ष ब्याज दरों को कम करने की मांग बढ़ रही है, ताकि फंड की लागत सस्ती हो जाए और निवेश व विकास को

बढ़ावा देने में मदद मिले। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि महंगाई को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांग और आपूर्ति का मुद्दा है। जबकि, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बैंकों से ब्याज दर में कमी की मांग की थी। इसके बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने दोहराया है कि महंगाई के खिलाफ केंद्रीय बैंक की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई हैं और ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं। इन स्थितियों में, एमपीसी अगली बैठक में क्या करेगी, मैं यहां उसकी भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। हालांकि, नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने में खाद्य मुद्रास्फीति को अलग से शामिल करने के लिए व्यापक परामर्श की आवश्यकता है। इस तरह के बदलाव के विभिन्न निहितार्थों पर चर्चा, बहस और निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत है। चूंकि मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण एक जटिल मुद्दा है, इसलिए विकास पर खाद्य मुद्रास्फीति के व्यापक निहितार्थ को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। आखिरकार मुद्रास्फीति एक अदृश्य कर है और यह वास्तविक आय और क्रयशक्ति को कम करती है, जो अपने आप में एक बाधा बनकर विकास को कम कर सकती है।

भारत जैसे विकासशील देश में, जहां रिजर्व बैंक की नीति में कई सामाजिक और विकास उद्देश्य शामिल हैं, इस विषय पर व्यापक परामर्श जरूरी है। वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के अनुसार, विकास के बड़े चालक राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि और राज्यों को अधिक पूंजीगत व्यय के लिए प्रेरित करना है। हमने वित्त वर्ष 2024-25 के मध्य बिंदु को पार कर लिया है। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय कम था। हाल के महीनों में पूंजीगत व्यय में सुधार हुआ है। हालांकि, इस साल अगले तीन-चार महीनों में पूंजीगत व्यय के चक्र को काफी तेजी से बढ़ाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, तो विकास दर में कमी आ सकती है। यह भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे संकेत हैं कि सरकार के कर राजस्व, खासकर प्रत्यक्ष कर में उछाल आने वाला है और यह बजटीय अनुमानों से ज्यादा हो सकता है। इसलिए संभवत: सरकार उधार की सीमा को पार किए बिना उच्च पूंजीगत व्यय का बोझ उठा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो कम राजकोषीय घाटा बाजार ब्याज दर पर दबाव को कम करने में मदद करेगा। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, अनिश्चितताओं और वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

नशीली दवा बेचने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई: शर्मा

उपमुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में हुई बैठक

रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में नशीली दवाओं के सेवन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने मंत्रालय महानदी भवन में प्रदेश में नशीली दवाओं के विक्रय एवं सेवन पर वैधानिक कार्यवाही करने और नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में इस आशय के निर्देश दिए गए। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा है कि नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए मेडिकल दुकानों का नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण करें तथा ऐसे मेडिकल शॉप जो वैधानिक नशीली दवाओं के कारोबार में संलग्न है उन पर त्वरित एवं कठोर कार्यवाही करें। ऐसे दुकानदारों पर एफआईआर करें तथा गिरफ्तारी की भी कार्यवाही करें। उपमुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों का सहयोग लेने की भी बात कही है।

बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जायसवाल ने नियंत्रक खाद्य एवं औषधि को पुलिस अधिकारियों से समन्वय कर ड्रग इंस्पेक्टर की टीम बनाकर लगातार दवाई दुकानों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुवा, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारीक, आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. प्रियंका शुक्ला, विशेष सचिव वित्त एवं सामान्य प्रशासन तथा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन चंदन कुमार सहित पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री की पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य ने तैयार की इकोरेस्टोरेशन पॉलिसी

● राज्य में जल्द लागू होगी यह पॉलिसी ● छत्तीसगढ़ होगा देश का दूसरा राज्य

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में जल्द इकोरेस्टोरेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। वन विभाग द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य होगा, जहां इकोरेस्टोरेशन पॉलिसी लागू होगी। अभी तक देश के एक मात्र राज्य केरल में यह पॉलिसी लागू है। इस पॉलिसी के लागू होने से राज्य में वनों का संवर्धन, जल स्त्रोतों का संरक्षण, मिट्टी का कटाव रोकने के साथ ही जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा।

यह जानकारी वनमंत्री केदार कश्यप एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नया रायपुर के मेफेयर में 'क्लाइमेट रेसिलिएंट छत्तीसगढ़ हरित और सशक्त भविष्य की ओर' विषय पर आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए दी। यह कार्यशाला छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र एवं सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट (सीड) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला का उद्देश्य छत्तीसगढ़ और पूर्वी राज्यों में जलवायु अनुकूलता और लो कार्बन आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान साझा करना और विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद स्थापित करना था।

क्लाइमेट रेसिलिएंट छत्तीसगढ़ हरित और सशक्त भविष्य की ओर' विषय पर आयोजित कार्यशाला में वन मंत्री और वित्त मंत्री हुए शामिल

कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों और उससे निपटने के महत्व पर चर्चा की। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 'जनजाति समुदाय सदैव जल, जंगल, और जमीन का संरक्षक रहा है। उन्होंने 1910 के भूमकाल आंदोलन का उल्लेख करते हुए जनजातीय समाज ने अंग्रेजों से अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए संघर्ष किया।

कश्यप ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी सरकार के सतत विकास लक्ष्यों का अभिन्न हिस्सा है। वित्त मंत्री चौधरी ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं को पर्यावरण संरक्षण के आदर्श उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किया।

उन्होंने कैलाश पर्वत और भगवान शिव-पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ उनके वाहन नंदी, बाघ, मूषक और मोर सबके एक साथ रहने के उदाहरण देते हुए सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व की महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, 'जलवायु परिवर्तन केवल चर्चा का विषय नहीं है; यह हमारे राज्य और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का माध्यम है।'

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रीन इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। श्री चौधरी ने ग्रीन इकॉनमी, बायोफ्यूल, और सोलर एनर्जी पर विशेष जोर देते हुए युवाओं को पर्यावरण नवाचारों और हरित निवेश में भागीदारी का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे ने कहा कि राज्य सरकार ने क्लाइमेट स्टूडियो की स्थापना को स्वीकृति दी है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नेटिव स्पीशीज के पौधों के रोपण, वन क्षेत्रों के विकास और वेटलैंड संरक्षण की योजनाओं पर जोर दिया। कार्यक्रम में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पर्यावरणविद, शिक्षाविद और नीति-निर्माताओं ने व्यापक चर्चा की।

आपात स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

रायपुर। आपात स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों पर यूनिसेफ के तत्वाधान में दिनांक 25 व 26 नवम्बर को दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का रायपुर में आयोजन किया गया । राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान सभी जिलों के जिला कार्यक्रम प्रबंधक, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक, अस्पताल सलाहकार व स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ कुल 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रक्षिक्षण के दौरान आपदा प्रबंधन की बुनियादी अवधारणाएं, अस्पताल तैयारियों की वर्तमान स्थिति, अस्पताल सुरक्षा ऑडिट चेकलिस्ट जैसे विषयों पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण के दौरान आपात स्थिति में स्वास्थ्य कर्मी/ विशेषज्ञों को कैसे तत्पर रहना चाहिए इस विषय पर बल दिया गया साथ ही मॉकड्रिल, आपातकाल में बचाव की प्रविधि व लाइव डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। राज्य स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न होने के उपरांत प्रदेश के सभी 5 संभागों में भी हेल्थ सिस्टम इमरजेंसी प्रीपेयेर्डनेस प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिससे कि अधिक से अधिक स्वास्थ्य कर्मी आपात परिस्थिति से निपटने में सक्षम हो सकें। मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विजय दयाराम के. ने बताया कि यह प्रशिक्षण प्रदेश में आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी व सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में किया गया बेहतर प्रयास है । इसके माध्यम से स्वास्थ्य संस्थाओं में आपातकालीन परिस्थिति के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया व प्रतिक्रिया समय को कम करने के साथ लोगों को बचाव की स्थिति हेतु तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

भाजपा का डीएनए संविधान विरोधी

रायपुर। भाजपा का डीएनए संविधान विरोधी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा ने तय कर लिया था कि यदि 400 से अधिक सीटें आ जाएगी तो संविधान बदल देंगे। देश की जनता ने भाजपा को 240 में समेट दिया तो उनकी मंशा पूरी नहीं हुई, संविधान बदलने के भाजपाई मंशा के कारण देश भर में भाजपा के खिलाफ माहौल बना तो भाजपा मजबूरी में संविधान की पैरोकार बनने का ढोंग करती है। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में देश को आजादी दिलाई, लोकतंत्र की बुनियाद नेहरू जी ने रखा, बी.आर. अंबेडकर के प्रयासों से हमें दुनिया का बेहतरीन, लिखित संविधान मिला लेकिन भाजपा की बदनीयती संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा तो मुखौटा है, उनके पित्रसंगठन आरएसएस को आरंभ से ही संविधान से शिकायत रही है। शिकायत समता और समानता के अधिकार से रही है। दलित, आदिवासी, पिछड़ों को अधिकार संपन्न बनाने से इन्हें शिकायत रही है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने के महज़ 4 दिन के भीतर ही आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने संविधान की कठोर आलोचना की थी, कहा था कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, उसके बाद से लगातार संघ प्रमुखों के संविधान विरोधी बयान आते रहे। के. सुदर्शन ने अप्रैल 2000 में आरएसएस संघचालक बनने के बाद कहा भारत के संविधान को समाप्त कर देना चाहिए उसके स्थान पर धर्म ग्रंथों पर आधारित संविधान लिखा जाना चाहिए। लगभग यही बात है मोहन भागवत ने भी कही संविधान में बदलाव की वकालत की, कर्नाटक की सभा में कहा कि दो तिहाई का बहुमत इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदला जा सके। आरएसएस के साथ-साथ भाजपा के ही तमाम नेताओं ने विगत लोकसभा चुनाव के दौरान 400 पार के नारे के समर्थन में संविधान बदलने की बात को स्वीकार किया। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, कर्नाटक के छह बार के भाजपा सांसद आनंद हेगड़े, फैजाबाद के लोकसभा प्रत्याशी लल्लू सिंह, तेलंगाना के भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी, नागौर के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा सहित अनेको भाजपा नेताओं ने संविधान बदलने के भाजपा के षड्यंत्र को उजागर किया।

छग वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम को जान से मारने की धमकी

रायपुर। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने आज आज़ाद चौक थाने पहुंचकर पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कुछ दिनों पहले सलीम राज ने आदेश जारी कर कहा था कि छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में जुमे (शुक्रवार) की नमाज के बाद होने वाली तकरीर के टॉपिक के लिए वक्फ बोर्ड की इजाज़त लेनी होगी, जिसके बाद से उन्हें लगातार धमकियों वाले कॉल और ई-मेल आ रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया था कि मुतवल्ली (मस्जिद की संपत्ति का प्रबंध करने वाला) इस नियम का पालन नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत कई मुस्लिम नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई थी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने बताया कि उन्हें धमकी देते हुए कहा गया कि तुमको 6 इंच छोटा कर देंगे। ऊपर गर्दन से छोटा होना है या नीचे से बता दो। उन्होंने आगे कहा कि, मैं इस तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैंने जो नियम बनाया है वह देशहित के लिए और सर्वहित के लिए है। इस नियम में साफ है कि तकरीर के दौरान राजनीतिक भाषण न हो, जिससे सामाजिक सौहार्द और वातावरण बना रहे। हमारे निर्णय के बाद 154 मुतवल्ली ने टॉपिक भेजा था जिसे हमने अप्रूव कर दिया है। जो वक्फ बोर्ड का अवगत नहीं कराएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

रेडी टू ईट के नाम पर भाजपा सरकार ने महिलाओं को ठगा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि रेडी टू ईट का काम महिला समूहो को देने का वादा 11 महीने बाद भी आज तक पूरा नहीं हुआ, उल्टे पूर्व के बकाए का भुगतान भाजपा सरकार आने के बाद दुर्भावना पूर्वक रोक दिया गया, छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के नाम पर महिलाएं ठगी गई हैं। साय सरकार बनने के बाद 2 लाख महिलाओं का रोजगार छिना गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं से रोजगार छीनने का काम कर रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रदेश में संचालित 10 हजार गोठानों में लाखों की संख्या में महिलाएं स्व सहायता समूह चलाकर अपनी आजीविका कमा रही थी। गमला, दीया, गौ-कास्ट, वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट के साथ ही रीपा परियोजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को उद्यमी बनने का अवसर मिला था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश की महिलाओं से काम छीन लिया गया, आज प्रदेश के लाखों महिलाओं के सामने रोजी-रोटी का संकट है, जीवन यापन के लिए आज प्रदेश की महिलाएं जूझ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार नए रोजगार तो छोड़िए पूर्व में जो रोजगार के अवसर थे उसमें भी कटौती करने का काम कर रही है।

टोकन कटने के बाद भी किसान धान नहीं बेच पा रहे

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि टोकन काटने के बाद भी किसान अपना धान बेच नहीं पा रहे है, क्योंकि टोकन कटने की तारीख से 3 से 7 दिन बाद धान बेचने के लिये किसानों को बुलाया जा रहा है। साथ ही सोसाइटियों ने 2 दिसंबर तक टोकन काटने के बाद टोकन काटना बंद कर दिया है। सोसाइटियों को निर्देश है कि एक दिन में अधिकतम 752 क्विंटल यानी 1880 कट्टा धान ही खरीदा जाना है। ऐसे में एक किसान का शेष धान के लिये उसको आगामी दिनों की तारीख दी जा रही है। सरकार भले ही घोषणा कर रही है पूरा धान खरीदेंगे, लेकिन जिस रफ्तार से खरीदी हो रही उससे किसान चिंतित है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि धान खरीदी केन्द्रों में फैली अव्यवस्था, बारदानों की कमी तथा टोकन के लिये सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों तथा मीलरों द्वारा धान का उठाव नहीं करने के कारण किसान परेशान है। समितियों में बारदाने की कमी है। सरकार ने कहा है कि 50 प्रतिशत नये 50 प्रतिशत पुराने बारदानों का उपयोग किया जाये। 50 प्रतिशत पुराने बारदाने समितियों में पहुंचे ही नहीं है, जिसके कारण धान खरीदी बाधित हो रही है।

मृतक प्रदीप उपाध्याय के जिम्मेदार अफसरों बचा रही है सरकार

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कलेक्ट्रेट के क्लर्क प्रदीप उपाध्याय के सुसाइड मामले में भाजपा सरकार जिम्मेदार अफसर को बचाने के लिए लीपापोती कर रही है। सुसाइड नोट को नकारने के लिये पुलिस द्वारा प्रेम संबंध की थ्योरी आगे किया जा रहा है ताकि दोषियों को बचाया जा सके। मृतक प्रदीप उपाध्याय के सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने अब तक उन तीन अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया है? जिसमें प्रदीप उपाध्याय ने अपने मौत के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया है। आत्महत्या के मामले में मृतक के सुसाइड नोट को मुख्य आधार माना जाता है और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। लेकिन यहां तो उलटी गंगा बह रही है पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बजाय उन अफसर को क्लीन चिट देने में लगी हुई है। पुलिस अपना काम करें न्यायालय का काम पुलिस न करें। प्रदीप उपाध्याय के मामले में भाजपा सरकार का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदीप उपाध्याय के कमरे से बरामद सुसाइड नोट में तीन बड़े अफसरो पर प्रताड़ित करने का जिक्र है। प्रदीप उपाध्याय ने तीनों अफसरो पर झूठी शिकायत करना एवं ब्राह्मण भगाओ कहकर अपमानित करने की आरोप लगाया है।

भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के रायपुर शाखा के लिए 15 सदस्य चुने गए

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला रेडक्रॉस सोसायटी अध्यक्ष डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर जिले में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के जिला शाखा रायपुर की सामान्य सभा आयोजित की गई। इसमें सर्वप्रथम सामान्य सभा की बैठक में कलेक्टर ने रेडक्रॉस के उद्देश्य, कार्य एवं कर्तव्य के बारे में जानकारी दी। निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव की प्रक्रिया को बताते हुए पूर्व में प्रकाशित दावा आपत्ति के बाद आजीवन एवं संरक्षक सदस्यों की अंतिम सूची प्रबंध समिति सदस्यता के लिए नामांकन फॉर्म भरा गया। 15 आवेदकों ने फॉर्म भरा और सभी को सर्वसम्मति से सदस्य का चयन किय गया। रायपुर शाखा के लिए राजू शर्मा, डॉ. प्रीति नारायण, डॉ. नवीन बगरेचा, डॉ. सत्यनारायण पाण्डेय, डॉ. राजेंद्र कुमार कश्यप,संतोष कुमार शर्मा, मानसिंह साहू, अश्वनी कुमार पांडे, दयानंद देवांगन, डॉ. अविनाश चतुर्वेदी, गजेंद्र डोंगरे, डॉ. श्वेता सोनवानी, बी.एल. ध्रुव, जशवरी सिंह बघेल एवं डॉ. पकंज किशोर को सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, सचिव जिला रेडक्रॉस सोसायटी, जिला रेडक्रॉस के संरक्षक, उप संरक्षक एवं आजीवन सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहे।

जोन 5 के वार्डों में लगाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड बनाने शिविर

रायपुर। नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 5 के वार्डों में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। 27 नवंबर को डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड में चंगोराभाटा के सांस्कृतिक भवन में शिविर का आयोजन किया जाएगा। 28, 29 नवंबर और 2 दिसंबर को ठाकुर प्यारेलाल वार्ड में पार्षद कार्यालय, डंगनिया पानी टंकी, बाजार चौक और पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्रमांक 41 में 3, 4, 5 दिसंबर को पार्षद कार्यालय सेक्टर 01 डी. डी. नगर, पं सुंदर लाल शर्मा वार्ड क्रमांक 42 में 6, 9 10 दिसंबर को सामुदायिक भवन अश्वनी नगर, सुंदर नगर, महंत लक्ष्मीनारायण दास वार्ड में 11,12,13 दिसंबर को यादव समाज भवन गोवर्धन चौक, पुरानी बस्ती, 16,17 और 19 नवंबर को वामनराव लाखे वार्ड में डे-केयर कुशालपुर एवं 20,23 और 24 दिसंबर को भक्त माता कर्मा वार्ड में वार्ड कार्यालय शितला तालाब श्रीराम नगर में शिविर का आयोजन किया जाएगा।

कृषकों को बैंक में लंबी लाइन लगाने से मिलने लगा छुटकारा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार में कृषकों को अब नकद राशि निकालने के लिए बैंकों में लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। किसानों को माइक्रो एटीएम प्रदान किए जा रहे है और उपार्जन केंद्रों में ही नकद राशि मिल रही है।

पत्रकारिता विवि में जनजातीय समाज के गौरवशाली अतीत पर कार्यशाला का आयोजन

रायपुर। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में आज जनजाति समाज का गौरवशाली अतीत- ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वनवासी विकास समिति के प्रांताध्यक्ष श्री उमेश कच्छप थे। अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. बलदेव भाई शर्मा ने की।

मुख्य अतिथि श्री उमेश कच्छप ने अपने उद्बोधन में कहा कि जनजातीय समाज में अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म हुआ है, जो हमें गर्वित करते हैं। उन्होंने जनजातीय संस्कृति की गहराई और आध्यात्मिकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस समाज में प्रकृति को सहेजने और उसके अनुरूप जीवन जीने की परंपरा है। जनजातीय परंपराएं भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। अपने देश के लिए संघर्ष करने की परम्परा जनजातीय समाज में प्रारंभ से रही है। भगवान विरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे अनेक महान नायकों ने अपना बलिदान दिया। जनजातीय संस्कृति में गहरी आध्यात्मिकता छिपी है। प्रकृति को सहेजकर, प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना। बड़े-छोटे, स्त्री-पुरुष में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना। यह मानना कि सब बराबर हैं और प्रकृति का उपहार सबके लिए है। ये बातें हमें इस समाज से सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं को इन परंपराओं का अध्ययन करने और इन्हें संरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बल्देव भाई शर्मा ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि इस प्रकार के आयोजन जीवन में प्रेरणा जगाने वाले होते हैं। वनवासी समाज का गौरवशाली अतीत और उनका ऐतिहासिक एवं सामाजिक ज्ञान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि हम इस ज्ञान को समझें और समाज के साथ सहभागिता बढ़ाएं। भारतवर्ष में वैदिक काल से अब तक जनजाति समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे देश के स्वतंत्रता आंदोलन हो या धर्म-संस्कृति के संरक्षण की बात हो, जनजाति समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जनजाति गौरव की जानकारी समाज में हर एक तक पहुंचे। प्रकृति पूजा के नाम पर जनजाति भाइयों को मूल धारा से अलग करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। जबकि हम तो प्रकृति को मां मानते हैं।

प्रो. शर्मा ने कहा कि भगवान विरसा मुंडा पूरे जनजाति समाज के प्रतीक हैं।

कृषि विवि की खेल प्रतिभाओं को निखारने हेतु दी जाएंगी हर संभव सुविधाएं : डॉ. चंदेल

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा है कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करने में विश्वविद्यालय द्वारा सभी आवश्यक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। डॉ. चंदेल आज यहां कृषि विश्वविद्यालय के स्पोर्टस काम्प्लेक्स में विश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ कर रहे थे। कुलपति डॉ. चंदेल ने खेल ज्योति प्रज्ज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आज संविधान दिवस के अवसर पर कुलपति डॉ. चंदेल ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पठन किया और सभी उपस्थित व्यक्तियों को संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई। विश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता - 2024 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण जोन के अंतर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालयों के 160 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। 26 से 28 नवम्बर, 2024 तक आयोजित होने वाली इस तीन दिवसीय विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न क्रीड़ा स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत व्यक्तिगत स्पर्धाओं में लम्बी कूद, ऊंची कूद, ट्रिपल जंप, भाला फेंक, गोला फेंक, डिस्क थ्रो, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, हर्डल दौड़ तथा 4X100 मीटर एवं 4X400 मीटर रिले दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.